अर्थशास्त्रियों ने चेताया, संसार से पहले घर सुधारो

संवाददाता

कानपुर,शनिवार। दयानन्द गर्ल्स कालेज के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा 'वैश्वीकरण व भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव' विषयक संगोष्ठी में आज यहां अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी कि वैश्वीकरण की अवधारणा पर अमल से पहले स्थानीय स्तर पर आर्थिक सुधार किये जाने चाहिए। संगोष्ठी में घरेलू व बाह्य उद्यमिता में सामंजस्य स्थापना पर जोर दिया गया।

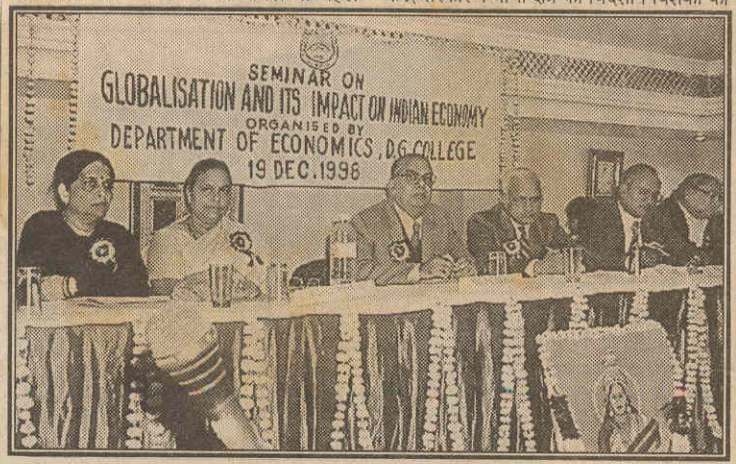

डी. जी. कालेज के अर्थशास्त्र विभाग के तत्वावधान में आयोजित सेमिनार में महिला कल्याण मंत्री प्रेमलता कटियार, डा.बी.एम.अग्रवाल, प्रो.टी.वी.एस.राममोहन राव व अन्य। डिजिटल फोटो- जागरण

संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए प्रदेश की महिला कल्याण व बाल पुष्टाहार मंत्री प्रेमलता कटियार ने कहा कि इस सदी के उत्तरार्ध में हु व्यापक परिवर्तनों के लिए वैश्वीकरण की प्रक्रिया उत्तरदायी है और भूमंडलीय गांव (ग्लोबल विलेज) की अवधारणा साकार होने के निकट है। उन्होंने कहा कि इन फैलते बाजार संबंधों का लाभ हमें तभी मिल सकता है, जब व्यापार शर्तें हमारे अनुकूल हों, किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। व्यापार महत्वपूर्ण है किन्तु यदि गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी व अशिक्षा के बुनियादी सवालों के समाधानों की संभावना यदि बढ़ते व्यापार के साथ जोड़ी जा सके, तो व्यापार आर्थिक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। वैसे भी भारत के लिए वैश्वीकरण आर्थिक दर्शन नहीं, आर्थिक विकास की रणनीति का एक अंग अवश्य हो सकता है। इसीलिए हमारी केन्द्र सरकार ने बीमा क्षेत्र को विदेशी निवेशकों को खोलने के साथ उनकी भागीदारी सिर्फ 26 फीसदी तक सीमित करने का प्रस्ताव किया है।

संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए दयानन्द एकेडमी आफ मैनेजमेन्ट स्टडीज के निदेशक डॉ.बी.एम.अग्रवाल ने कहा कि आर्थिक सुधार जरूरी हैं किन्तु पहले आंतरिक घरेलू क्षेत्र में सुधार किये जाने जरूरी हैं। घरेलू सुधारों के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस वैश्वीकरण प्रक्रिया को भारत में लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि घरेलू व बाह्य उद्यमिता में सामंजस्य स्थापित किया जाना जरूरी है। इसके लिए पहले चरण में उच्च वरीयता के कुछ क्षेत्र चयनित किए जा सकते हैं। हमारा वित्तीय पक्ष मजबूत किया जाना चाहिए और पहले पूरा जोर घरेलू बाजार पर दिया जाना चाहिए।

संगोष्ठी के मुख्य वक्ता भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के मानविकी विभाग के प्रवक्ता व प्रमुख अर्थशास्त्री टी.वी.एस. राम मोहन राव ने कहा कि हमारे सामने आंतरिक स्तर पर सामाजिक न्याय की स्थापना बड़ी चुनौती है, पहले हमें इस पर जोर देना चाहिए। वैश्वीकरण की अवधारणा के सार्थक सदुपयोग के लिए उत्पादन व आधारभूत ढांचे को प्राथमिक वरीयता के रूप में मान्यता देनी होगी और साथ में एक जवाबदेह सरकार भी आवश्यक है। जीवन के हर क्षेत्र में सूचना तकनीक हावी हो रही है और संचार क्रान्ति अंतर्राष्ट्रीय बदलाव ला रही है। ब्रिटिशराज के कड़वे अनुभवों ने हमें लगभग 50 वर्षों तक वैश्वीकरण तक दूर रखा है और आज हमारे सामने उपस्थित विषण सामाजिक परिस्थितियों का सरल समाधान तात्कालिक रूप से उपलब्ध नहीं है। सरकार के पास उपयुक्त प्रबंधकीय संसाधन नहीं है और परिणाम स्वरूप चारा व दूरसंचार घोटाले जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। औद्योगिक प्रबंधन सलाहकार पी.एस.सत्संगी के सवालों के जवाब में डा.राव ने कहा कि तथाकथित पश्चिमी संस्कृति संचार तकनीक के संवर्द्धन के कारण ही हमारे जीवन का हिस्सा बन गयी है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के ही प्रो.बिनायक रथ ने कहा कि सरकार की वैश्वीकरण प्रक्रिया से सामाजिक क्षेत्र पर ही दुष्प्रभाव पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय अनुदानों व निजी निवेश की कमी घरेलू बाजार के ही आड़े आएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और बड़ा संकट बनेगी। ऐसी स्थितियों में पहले हमें अपने घरेलू बाजार पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हमारी जनसंख्या का 70 प्रतिशत हिस्सा भूमिहीन खेतिहर मजदूर व छोटे किसान हैं, जिन्हें इस वैश्वीकरण से कोई सीधा लाभ नहीं है और निजी बाजार तकनीक इनके विकास में बाधक ही साबित होगी। प्रो.आर.आर.वर्थवाल ने कहा कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वैश्वीकरण एक शक्तिस्थापना का मार्ग भर है और अमीर देश इसके माध्यम से दबाव बनाते हैं। इसलिए इसका विश्लेषण करते समय राजनीतिक व आर्थिक दोनों पहलुओं पर ध्यान दिया जाए। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम के महाप्रबंधक एम.पी.मिश्रा ने कहा कि हमारे आर्थिक सुधार शुरू कर मझदार में छोड़ दिए गए। हमें आर्थिक मजबूती के साथ राजनीतिक व सामाजिक मजबूती भी चाहिए। डी.जी.कालेज की प्रवक्ता डा.मुकुलिका हितकारी ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था को शेष विश्व से जोड़ने की आवश्यकता है और भारत को अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। सामाजिक वरीयताओं का पुनर्निधारण कर आर्थिक शोध व विकास, स्वास्थ, शिक्षा आदि क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए। डी.एस.एन. कालेज उन्नाव के हिलाल अहमद ने कहा कि भारत के लिए वैश्वीकरण अनावश्यक प्रक्रिया थी किन्तु परिस्थितिवश हमें इसे स्वीकार करना पड़ा। हमने इससे लाभ भी उठाया है फिर भी चैतन्यता आवश्यक है। अतिथियों का स्वागत प्राचार्या डा.कमल द्विवेदी, धन्यवाद अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष मालती निगम व संचालन कार्यक्रम संयोजक साधना सिंह ने किया।

SEPTEMBER 27, 2003

DAINIK JAGRAN

नदियाँ जोड़ने व भूजल सहेजने से ही जल संकट का समाधान

संवाददाता, कानपुर

नदियां जोड़ने व भूजल सहेजने से ही जल संकट का स्थायी समाधान खोजा जा सकता है। भारत सरकार द्वारा इस आशय की परियोजना शुरू तो की गयी है किन्तु व्यापक जनसहभागिता के बिना इस परियोजना की सफलता संदिग्ध होगी।

ईको फ्रैण्ड्स के तत्वावधान में सेंट मैरीज कांवेंट में जल की गुणवत्ता व अभाव विषयक कार्यशाला में दिल्ली की द इकोलॉजिकल फाउंडेशन के डॉ.सुधींद्र शर्मा ने कहा कि नदियों को जोड़ने की भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना समयबद्ध ढंग से पूरी होना अत्यंत आवश्यक है।

इस योजना की सफलता से जल संकट का स्थायी समाधान हो सकता है, किन्तु इसके लिए आम नागरिकों की व्यापक सहभागिता व दृढ़ इच्छाशक्ति जरूरी होगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक मूल्यों में कमी व राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में इस योजना का पूरा होना ही संदिग्ध है। आईआईटी के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रवक्ता डॉ.बिथिन दत्ता ने कहा कि 1972 में प्रस्तावित नदियों को जोड़ने की परियोजना पर अब काम शुरू हो सका है। 56 खरब रुपए लागत वाली यह योजना 2016 तक पूरी हो जाएगी, जिससे निश्चित रूप से संभावित जल संकट से मुक्ति मिल जाएगी।

इससे पूर्व उद्घाटन करते हुए आईआईटी के अर्थशास्त्र विभाग के प्रवक्ता डॉ. बिनायक रथ ने कहा कि भारत में जल संसाधनों के लिए तीन 'पी' सर्वाधिक आवश्यक हैं। इनमें 'प्रापर प्लानिंग' (उचित नियोजन), 'पॉलि- टिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक विल' (राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति) व 'पीपुल्स पार्टिसि-पेशन' (जनसहभागिता) शामिल हैं। इनके द्वारा भारत ही नहीं पूरे विश्व में जल संकट का स्थायी समाधान हो सकता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बीपी शुक्ला, डॉ.अनिल दीक्षित, डॉ.एन बोसवाल, राकेश जायसवाल आदि ने भूजल संरक्षण को संभावित जल संकट से निपटने का मूल आधार बताया।

■ सेंट मैरी स्कूल में कार्यशाला का दीप जलाकर शुभारम्भ करते मुख्य अतिथि विनायक रथ। जागरण

उन्होंने कहा कि भूजल को प्रदूषणमुक्त रखना भी सर्वाधिक जरूरी है। संचालन पीजी थॉमस ने किया।

हरिद्वार का गंगाजल, पूजा सामग्री पॉली पैक

हमारे संवाददाता, कानपुर

गंगा तट पर बसे नगर का यह दुर्भाग्य ही है कि नवदुर्गा पर बाजार में हरिद्वार का बोतलबंद गंगाजल बिक रहा है। इसी तरह नवग्रह बनाने में काम आने वाली दालों से लेकर सारी पूजन और खाद्य सामग्री पॉली पैक में उपलब्ध है।

हरिद्वार के गंगा जल विक्रेताओं ने इसमें गुलाब जल भी मिल रखा है। 5 से 15 रुपये की शीशी पूजन के प्रयोग के लिये खासतौर पर बेंची जा रही है। मोतीझील में प्रज्ञा मिशन की पूजन सामग्री के विक्रेता यज्ञ कुमार मिश्र ने बताया हरिद्वार के गंगा जल से भक्तों में शुद्धता का भाव जागता है। नवग्रह बनाने में काम आने वाली दालों से लेकर सारी पूजन और खाद्य सामग्री पॉली पैक आ रही हैं। तमाम कंपनियों ने इनके पैकेट बाजार में उतारे हैं। जौ, तिल, कलावा, कपूर, चावल, पीली सरसों, रुई, रुई की बाती, जनेऊ, सुपारी, मारकीन, टून कपड़ा, रोली सिंदूर के साथ माँ के वस्त्र भी पॉलीपैक में मौजूद हैं। इसी कड़ी में ऊँ, सतिया, शुभलाभ, शुभ चरणों के चित्र वाले सुविधाजनक स्टीकर दुकानों में मिल रहे हैं।

अफगानी गोंद से महंगी हवन सामग्री

कानपुर: नवरात्र पर हवन सामग्री तीस से चार सौ रुपये किलो बिक रही है। अफगानिस्तान के गोंद और भूटान की काई मिली ये समिधा जितनी महंगी है उतनी ही महकी हुई है। लकड़ी के बुरादे से ज्यादा जड़ी, लकड़ियां, फूल, पत्तियां और खाद्य पदार्थ मिलाये जाते हैं। इसमें बाहमी, देवदार, नागर मोठ, खस, शंखपुष्पी, भोजपत्र, अनारदाना, सुगंध कोकिला, सुगंध बाला, हाउबेर, तोमड़, कुसुम, टेसू, सुगंध मंत्री, बेलगिरी, जौ, तिल, शक्कर, गुड़, शहद, देशी घी, लौंग, इलाइची, लाल-सफेद चंदन, चावल, काजू बादाम, चिरौंजी, गरी, छुआरा आदि के साथ अफगानिस्तान का गोंद भी इसमें पड़ता है जिसे गुग्गुल कहा जाता है, लेकिन बबूल आदि पेड़ों के नकली गोंद को व्यापारी गुग्गुल के नाम से बेंच रहे हैं। हालांकि चार सौ रुपये तक महंगी हवन सामग्री में गुग्गुल के साथ भूटान की काई मिली है जिसे छबीला कहा जाता है। देश में इसी तरह की काई चेन्नई से आती है।

योग्य खाद्य पदार्थों में दो दिन में जबरदस्त उछाल आया है। सिंघाड़े का आटा 38 रुपये से 44 पर पहुंच गया है। कूटू का आटा 36 से 40 पर और आरारोट वाला साबूदाना 24 से 26 व असली साबूदाना 30 से 36 रुपये किलो पहुंच गया है। 9 रुपये किलो की जौ 12 में है जबकि कच्ची मूंगफली 44 से 52 रुपये किलो तक चढ़ गयी है। कच्चा नारियल 8 से 10 रुपये और सूखा नारियल दस रुपये में है। सेव, केले और मौसमी की कीमतें भी चढ़ गयी है।

तांबे का नवग्रह यंत्र भी बिक रहा है। दुर्गा माँ की ऐसी तस्वीरें भी मिल रही हैं जिनमें रौशनी भी है और आरती भी बजती है। इसके साथ ही वंदनवार और मालायें भी उपलब्ध हैं।

सवा करोड़ के कैसेट आये: टी सीरीज, टिप्स, वीनस सहित एक दर्जन से ज्यादा कंपनियों ने सवा करोड़ रुपये से ज्यादा के कैसट केवल नगर के बाजार में झोंके हैं। इनमें फिल्मी गीतों पर माँ दुर्गा के गीत और रात्रि जागरण के गीत मौजूद हैं। एचएमवी ने फिल्मों के प्रसिद्ध दुर्गा गीतों के अलग कैसेट जारी किये हैं।

फलाहार हुआ महंगा: व्रत

साक्ष्य सहित शिकायत पर उत्पादनकर्ता पर कारवाई

दैनिक आज (आज समाचार सेवा) 16.6.99

कानपुर, १५ जून। उपभोक्ता द्वारा साक्ष्य सहित शिकायत पर उत्पादन कर्ता पर कारवाई की जायगी। यह बात भारतीय मानक ब्यूरो के उप निदेशक ए.के.बेरा ने सुकलन पुरवा में सम्पन्न हुए ग्रामीण उपभोक्ता सम्मेलन में कही।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए आई.आई.टी. के अर्थशास्त्री डा.विनायक रथ ने कहाकि सरकार की नीतियों गांवों के विकास कार्यक्रम का समावेश होना चाहिए ताकि गांव का विकास हो सके। प्रायः बरसात में गांव में सड़के न होने से आवागमन बाधित हो जाता है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भारतीय मानक ब्यूरों के निदेशक ने कहाकि यद्यपि वर्तमान दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का निर्माण बिना आई.एस.आई. प्रमाणन के संभव नहीं है। फिर भी थोड़े से लालच में उपभोक्ता नकली उत्पादन कर्ता के जाल में फंसकर शोषण करा बैठता है। आज आई.एस.आई. द्वारा प्रमाणित हर वस्तु घर में उपलब्ध होने के बाद भी बिना जानकारी ग्राहक ठगा जाता है। आई.एस.आई. मोहर की पहचान के लिए ध्यान से देखने पर अक्षरो की एकरुपता तथा मुहर के नम्बर से असली-नकली की पहचान हो सकती है।

कार्यक्रम का संचालन उपभोक्ता परिषद के निदेशक ध्रुव कुमार शुक्ला ने किया।

उपभोक्ता सम्मेलन का आयोजन

कानपुर, 15 जून। उपभोक्ता परिषद के तत्वावधान में ग्रामीण उपभोक्ता सम्मेलन व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सुकलन पुरवा में किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए आई.आई.टी. के अर्थशास्त्री विनायक रथ ने कहाकि सरकार की नीति निर्माण में गांवों की समस्याओं का समावेश होना आवश्यक है। उन्होंने कहाकि देश को आजाद हुए पचास वर्ष हो जाने के बावजूद गांवों का विकास नहीं हो पाया है।

हिन्दुस्तान 16.6.99

Consumer Forum

17.6.99

THE CONSUMER Council, today organised a conference at Sakulan Purwa in Kanpur Dehat. The conference was presided over by director, Indian Standard Bureau, Mr RN Sharma. The local participants highlighted the problems being faced by them for the schooling of their children and medical facilities. The conference was inaugurated by Dr Vinayak Rath of the IIT-Kanpur, who laid stress on consumers activities. The programme was conducted by Dhru Kumar Shukla.

Economist highlights villagers' problems

पायनियर 17.6.99

KANPUR: NOTED ECONOMIST Vinayak Rath of the Indian Institute of Technology, while addressing the rural consumer conclave-cum-training camp at the Kanpur dehat, underlined the need for inclusion of rural problems in the policy planning.

He said that it was shocking that despite 50 years of Independence no development had taken place in the villages. He said people and the government both were equally responsible for the present plight of the rural areas.

Mr Rath claimed that political will was missing for the uplift of villages. He said Uttar Pradesh was the worst affected as there was no awareness in comparison to other states. He said that there had been substantial progress in the field of education but the qualified people preferred to go abroad depriving the Indians of the benefits which they could offer to them

He said the state government had spent Rs 1 crore on papers in Dibiapur but in fact there had hardly been two per cent progress there. Addressing the function, Director of Indian Standards Bureau RN Sharma admitted that the people were themselves at fault for keeping progress at bay from hamlets. Highlighting the problems of Sakulan Purva village, he said it had a primary school only and students had to cross a river if they wished to pursue higher studies. Villagers, who were present there, said that as there was no bridge over the river they had to face a lot of problems in taking serious patients to government hospitals. Besides, they were not able to take their produce to the centres as a result they did not get proper return of their product, they said. Later, director of Upbhokta Parishad Dhruv Kumar Shukla also spoke on the occasion.

Staff Reporter

ग्रामीण उपभोक्ता सम्मेलन में अभावों पर चर्चा

राष्ट्रीय सहारा 16.6.99

उपभोक्ता परिषद ने शोषण से बचने के उपाय बताये

सहारा समाचार

कानपुर, 15 जून। उपभोक्ता परिषद के तत्वाधान में सुकलनपुरवा जनपद देहात में हुये ग्रामीण उपभोक्ता सम्मेलन मे क्षेत्रीय उपभोक्ताओं ने विकास के अभाव का खाका खींच डाला। शिक्षा, चिकित्सा व बाजार के अभाव मे क्षेत्रीय ग्रामीणो की आर्थिक अवस्था सुदृढ नही हो पा रही है। ग्रामीणो की समस्यायें सुनने के बाद परिषद के निदेशक ने शोषण से बचने के उपाय बताये। इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक आर.एन. शर्मा ने की।

क्षेत्रीय उपभोक्ताओं ने बताया कि गांव मे सिर्फ प्राइमरी स्कूल ही है। उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को नदी पार करके बाघपुर जाना पड़ता है जो कि लड़कियों के लिये सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति मे शिक्षा के अभाव मे लड़कियों की शादी ब्याह करने मे बहुत कठिनाई आती है। हर सामान खरीदने के लिये बाघपुर ही जाना पड़ता है जो नदी पुल न होने के कारण बहुत ही दिक्कत तलब है।

यहां का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी मैथा ब्लाक मे ही है। वहां जाने का रास्ता भी नदी पार करके ही है। गम्भीर मरीज को तो हम ले ही नहीं जा पाते है। यातायात साधनों के अभाव में हम अपनी पैदावार का सही मूल्य भी नहीं पा पाते। बरसात मे इस नदी का पानी गांव तक आ जाता है। गांव में बिजली न होने के कारण अन्य तमाम असुविधाओं के साथ-साथ हम लघु, कुटीर उद्योग लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति भी नहीं सुधार पा रहे है।

राशन की दुकान बाघपुर मे होने के कारण हम लोगों को होली, दिवाली में ही शक्कर, मिट्टी का तेल मिल पाता है। जन प्रतिनिधियों ने हमारी समस्याओं के सम्बन्ध मे चुनाव लड़ते समय आश्वासन तो बहुत दिए परन्तु समाधान आज तक नही हुआ क्योंकि दुबारा उनके दर्शन नही मिल पाते।

ध्रुव कुमार शुक्ल, निदेशक उपभोक्ता परिषद ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यरत उपभोक्ता संरक्षण फोरमों मे किसी प्रकार का शोषण होने पर शिकायत करने के तरीके को विस्तार से समझाते हुए उसके महत्वपूर्ण फैसलों का उदाहरण भी प्रस्तुत किया तथा उपरोक्त समस्याओं के समाधान मे परिषद का पूर्ण योगदान मिलने हेतु भी आश्वासन दिया।

डा. विनायक रथ (अर्थ शास्त्री) आई.आई.टी., कानपुर ने शुभारम्भ करते हुए कहा कि सरकार की नीति निर्माण मे गांवों की समस्याओं का समावेश होना आवश्यक है। देश को आजाद हुए लगभग 50 वर्ष हो जाने के बावजूद जो विकास गांवों का होना चाहिए था नहीं हुआ है। प्रातः बरसात मे गांवों में आना जाना सम्भव नहीं होता। यहां की तमाम ऐसी समस्याएं है जिन्हें देखकर दिल दहल उठता है। देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले हमारे उ.प्र. मे जागृति नहीं है।

उन्होंने कहा कि विकास न होने में हम व सरकार बराबर के साझीदार है। सरकारी योजनाओं से काफी लाभ हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश काफी प्रगति हुई है परन्तु हमारे देश का शिक्षित व्यक्ति प्राथमिकता पर विदेश जाना पसन्द करता है। उसके विदेश जाने से अपने देश को उसकी सेवाएं नहीं मिल पाती। बैंकों को गांवों में खुलना चाहिए जिससे उनका लाभ वहां के विकास में लग सके लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। डा. रथ ने बताया कि दिबियापुर में एक करोड़ रूपया सरकार ने कागजों पर खर्च कर डाला परन्तु वास्तविकता में लोगों के असली लाभ की योजनाएं 2 प्रतिशत ही अमली जामा पहन सकी।

ए.के. बेरा, उप निदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो कानपुर ने मुख्य वक्ता के रूप मे सम्बोधित करते हुए कहा कि वस्तु खरीदते समय आप विज्ञापन से या दुकानदार की लुभावनी बातों से प्रभावित होकर अथवा लोगों से जानकारी प्राप्त कर वस्तु को खरीदते है। व्यापारी अपने फायदे के अनुसार ग्राहक को सामान बेंचता है। खरीददारी करते समय हमें क्या देखना चाहिए इसकी ठीक से हमे जानकारी नहीं है। खाने की वस्तु को तो आप चख कर भी देख सकते है परन्तु पशु आहार तो आप चखकर भी नहीं समझ सकते।

भारतीय मानक ब्यूरो बिजली के 100 वाट के बल्ब को। घण्टे मे कितनी बिजली खानी चाहिए, वह कितने दिन चलेगा, कितनी रोशनी देता है आदि चेक करने के बाद ही लाइसेन्स देता है। 16,000 मानक तैयार किए जा चुके है। हर तीन महीनें में फैक्ट्री मे तथा प्रायः बाजार से खरीदकर हम चेकिंग करते रहते है। आप आई.एस.आई. मार्क वस्तु को खरीदकर यदि सन्तुष्ट नहीं है तो हमे सप्रमाण शिकायत करे। हम उस पर तुरन्त कार्यवाही करेगें और शिकायत सही होने पर आपको सही वस्तु दिलाने के साथ-साथ उस उत्पादनकर्ता का लाइसेन्स सस्पेन्ड आदि सख्त कार्यवाही की जाती है। कृपया आई.एस.आई. मुहर लगी वस्तु ही खरीदें।

आर.एन. शर्मा निदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो कानपुर ने अध्यक्ष पद से सम्बोधित करते हुए कहा कि गांवों में हम चकरोड को काटकर पगडंडी बनाने मे जरा सा भी संकोच नही करते इसका मतलब यह है कि हम रास्ते को समाप्त करके विकास को गांवों तक नही पहुंचने देना चाहते है। आई.एस.आई. की नकली असली मुहर को पहचानने के लिए विशेष रूप से तीनों अक्षरों (आई.एस.आई.) में एकरूपता को ध्यान से देखे तथा हर मुहर पर नम्बर पड़ा होता है।

जीवन में दैनिक उपयोग में आने वाली तमाम वस्तुएं जैसे हैण्डपम्प, क्रेसर, सीमेन्ट, बिजली के अनेक उपकरण, बिस्किट आदि का निर्माण बगैर आई.एस.आई. प्रमाणन के सम्भव ही नहीं है। मां या जानवर का दूध बच्चों के लिए हानिकारक सिद्ध हो जाने के कारण बेबी मिल्क पाउडर आवश्यक हो गया है।

इसका भी निर्माण बगैर हमारे प्रमाणन के सम्भव नहीं है। आई.एस.आई. हर घर मे मौजूद है परन्तु आप उसके बारे में जानते ही नहीं है और भटकते रहते हैं। गलत उत्पादनकर्ता बहुत चालाक बनता है उसको हम आपके सहयोग से भी पकड़ सकते है। हमारे विभाग की सेवाएं हमेशा आपके लिए उपलब्ध है।

श्री शिशु पाल सिंह गौर ने बताया कि जो उपभोक्ता अन्धा होता है उसके शोषण की कोई सीमा ही नहीं होती। मरणोपरान्त नेत्रदान कर एक अन्धे को शोषण से मुक्ति दिलाएं। अन्त मे उन्होने आभार व्यक्त किया।

19.08.97

विलम्बित न्याय समस्या एवं निदान पर परिचर्चा सम्पन्न

कानपुर, १८ अगस्त(वि.)। उपभोक्ता परिषद के तत्वावधान में विलम्बित न्याय समस्या एवं निदान पर परिचर्चा लोकमान्य तिलक पुस्तकालय, अशोक नगर में डा. जगदीश शर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

परिचर्चा शुरू करते हुए नगर के वरिष्ट अधिवक्ता एन.के.नायर ने कहा कि वर्तमान स्थिति में भ्रष्टाचार तथा कार्य को किसी न किसी प्रकार विलम्बित करने की मनोवृत्ति को दूर किए बिना इस समस्या का निदान नहीं हो सकता जस्टिस एट योर डोर स्टेप के नारे का खोखलापन प्रदर्शित करते हुए उन्होंने सर्विस एण्ड इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल्स व कन्सीलिएशन तथा लेबर कोर्ट में कर्मचारियों के होने वाली दुर्दशा तथा विलम्बित न्याय के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की।

डा. वी.एन.सिंह ने कहा कि वोटों की राजनीति को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीशों की नियुक्तियां की जाती है। डा. यतीन्द्र तिवारी 'प्राचार्य अर्मापुर पोस्ट ग्रेजुएट कालेज ने बताया कि न्यायिक प्रक्रिया के प्रति जो निष्ठा है वह प्रक्रिया की जटिलता के कारण प्रभावित होने लगी है। जिससे असंतोष जन्म लेता है। उन्होंने पूर्ववत यथावत की स्थिति पर चिन्ता करते हुए इसे समाज की प्रगति में अवरोधक की संज्ञा दी।

डा. विनायक रथ आई.आई.टी ने राष्ट्रीय स्तर पर लोवर हाई कोर्ट स्तर पर २५ मिलियन पेंडिंग केसेज का जिक्र करते हुए उन्नाहार रायबरेली के निकट २१ गांवों गाजिया बाद में दादरी इटावा में दिबियापुर के अपने सर्वे के आधार पर बताया कि भूमि अधिग्रहण के १७२६ मामलों में १२०६ मुकदमे लगभग १० साल पूर्व दायर किए गए जिनका निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। डा. रथ ने आगे कहा कि वर्तमान न्याय प्रणाली एडवर्सरी माडल आफ जस्टिस के रूप में जानी जाती है। लोक अदालत की व्यवस्था को उन्होंने उपयोगी बताया।

बृजेश सिंह एडवोकेट ने बताया कि ३१ दिसम्बर ९७ तक प्रदेश के जिला फोरमों में १५०४५७ वाद दाखिल हुए जिसमें से ९५९५० ही निस्तारित हो सके। स्टेट फोरम में ३१.दिसम्बर '९६ तक १७९२ नए मुकदमे दाखिल हुए जिसमें से ८३६ का निर्णय हो सका तथा १३०८७ अपीले दायर हुई जिनमें से २९३६ का निर्णय हो सका। विश्व नाथ कपूर वरिष्ट एडवोकेट ने जोर देकर वर्तमान न्यायिक प्रणाली को भारत की मिट्टी व जनमानस के स्वभाव के विरुद्ध बताया। उन्हों। विधि शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार पर बल दिया।

डा. जगदीश शर्मा ने अध्यक्ष पद से बोलते हुए आज की परिचर्चा में अपने विचारों को बिन्दुवार सघन चर्चा करने पर बल दिया।

परिचर्चा में प्रमुख रूप से बंकपाणि बाजपेई एडवोकेट डा. आर.आर.वर्धकल सरदार गुरमुख सिंह एडवोकेट गुलाब शंकर दीक्षित अतहर नईम डा. जे.पी.तिवारी राजेन्द्र श्रीवास्तव बंका राज त्रिपाठी शिशु पाल सिंह गौर सरदार हरभजन सिंह खण्डूजा मिश्री लाल गुप्ता श्रीमती पदमा शुक्ला विनय कुमार आदि ने भाग लिया।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए ध्रुव कुमार शुक्ल निदेशक उपभोक्ता परिषद ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

उपभोक्ता सड़कों पर चलने के अधिकार के लिये संघर्ष करें

दैनिक जागरण 28-2-94

(संवाददाता)

कानपुर, रविवार। महानगर की सड़कों पर अव्यवस्थित यातायात के लिये उपभोक्ताओं को एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिये, सड़कों पर चलना उनका मौलिक अधिकार है किन्तु अतिक्रमण के कारण उपभोक्ता इस अधिकार से वंचित हो रहे हैं।

उपरोक्त विचार आज यहां उपभोक्ता परिषद द्वारा यातायात व्यवस्था समस्यायें एवं सुझाव, विषय पर आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने व्यक्त किये।

संगोष्ठी की शुरुआत करते हुये नगर महापालिका (ट्रैफिक सेल) के अधिशाषी अभियंता प्रदीप तिवारी ने कहा कि महापालिका द्वारा फुटपाथ के ऊपर दुकानों के लिये जगह का एलाटमेंट उसके सदुपयोग के लिये किया गया था किन्तु आज वही दुरुपयोग में परिणत हो गया है उन्होंने कहा कि टेम्पो तो गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिये बना था, यात्रियों के लिये नहीं। उन्होंने कहा कि अभियान्त्रिकी, शिक्षा एवं अतिक्रमण इस समस्या के तीन पहलू हैं। सड़कें आज स्वामित्वहीन हो गयी हैं जो जहां पैसा चाहे उपयोग कर रहा है लेकिन उनके लिये दंड की व्यवस्था नहीं है, सड़कों के साथ खुले आम अनाचार हो रहा है। सड़कों के उपभोक्ताओं को सड़क पर चलने का हक हर हाल मे मिलना चाहिये।

उन्होंने नेताओं पर भी प्रहार करते हुए कहाकि वह अतिक्रमण नहीं हटने देते सभासदों ने भी अपनी मर्जी से कई गलत काम करवाये जिन्हें नहीं होना चाहिए था।

आई. आई. टी. के प्रोफेसर अर्थशास्त्री डा. विनायक रथ ने कहाकि इस समस्या के प्रमुख अंग तकनीकी, प्रबंधकीय, वित्तीय तथा सामाजिक हैं। उन्होंने कहाकि यातायात सुधार के लिए योजनायें तो बनीं लेकिन उनका काम नहीं हुआ क्योंकि इस काम वाले अधिकारी का मुख्य काम पैसा पैदा करना है। अधिकारी समस्याओं के हल में रुचि नहीं लेते।

डा. रथ ने कहाकि उपभोक्ता संगठनों को इस मामले में पहल करनी चाहिए।

संगोष्ठी का संचालन उपभोक्ता परिषद के निदेशक ध्रुव कुमार शुक्ला तथा आभार कार्यक्रम संयोजक विपिन बिहारी मिश्र ने किया। संगोष्ठी में डा. वी. एन. गिल, अमीनुद्दीन अहमद, सुमंत मिश्रा, डा. पूर्णिमा तिवारी, ब्रजेश सिंह, डा. सुन्दरलाल वर्मा, शंकर प्रताप सिंह आदि थे।

Discussion on traffic management held

पत्रिका 28-2-94

Staff Reporter

Kanpur

ROADS IN the city are ownerless, for anyone can set up his shop on them and still go unpunished.

This was stated by Mr Pradip Tiwari, executive engineer (traffic cell) of Nagar Mahapalika while speaking at a seminar on 'City Traffic Management-Problems and Suggestions' organised by Upbhokta Parishad in Misra Market at Sisamau on Sunday.

Mr Tiwari, while talking of traffic, regretted that the intention of the Mahapalika by allotting space over the footpaths for their better utility had resulted in their misuse. The tempos which were meant for transport of goods were carrying passengers. He said that the user of the road must get his right.

Mr Ravi Kumar Tiwari, Asstt Director, Information said that the population explosion was the main contributing factor of the traffic problem in the city.

Dr Vinayak Rath, the IIT economist who presided over the seminar opined that technical, managerial, financial and social were the pivotal parts of the problem. The plan was not implemented because the incoming official was basically concerned with money-spinning.

28.02.94

यातायात व्यवस्था पर गोष्ठी खानापूरी साबित हुई

अमर उजाला 28-2-94

(कार्यालय संवाददाता)

कानपुर, २७ फरवरी। उपभोक्ता परिषद के तत्वावधान में आज यहां 'यातायात व्यवस्था समस्या एवं सुझाव' विषय पर आयोजित परिचर्चा में लोगों की भागेदारी न के बराबर रही। मात्र डेढ़ दो दर्जन लोगों के बीच केवल खानापूरी की गयी। परिचर्चा में पुलिस महानिदेशक कार्यालय से सम्बद्ध पुलिस उप महानिरीक्षक डी.एन. सामल के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने की घोषणा की गयी थी लेकिन वे नहीं आए। गोष्ठी में निष्कर्ष निकला कि अगर नागरिक सचेत न हुए तो सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाएगा।

मिश्रा मार्केट सीसामऊ में आयोजित इस परिचर्चा का शुभारम्भ करते हुए नगर महापालिका ट्रैफिक सेल के अधिशासी अभियन्ता प्रदीप तिवारी ने कहा कि यातायात व्यवस्था के संबंध में चर्चा करते समय सड़क, सड़क का उपयोग करने वाली तथा फुटपाथ पर विचार करना चाहिए। फुटपाथों पर दुकानों का आवंटन जगह के सदुपयोग की विचारधारा से किया गया था लेकिन आज इसका दुरुपयोग होने लगा है।

उन्होंने कहा कि सड़क स्वामित्वहीन हो गयी हैं। जो जहां चाहे सड़क की दुकान के रूप में प्रयोग करने लगता है। ऐसे लोगों के लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है। सड़कों का आवश्यकता से अधिक दुरुपयोग करके आज विषम परिस्थितियां पैदा कर दी गयी हैं। सड़क के उपभोक्ता से सड़क पर चलने का हक छीना जा रहा है। उसे यह हक मिलना ही चाहिए।

बिजली मजदूर यूनियन के उपाध्यक्ष अमीनुद्दीन अहमद का कहना था कि उपभोक्ताओं के सजग सशक्त आंदोलन के बिना किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। समस्या को यथास्थान रोकना ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। डा. बी.एन. सिंह का कहना था कि दोषी कौन है यह तय कर पाना बड़ा मुश्किल है। फुटपाथ, सड़क, बस, टैम्पो तथा रिक्शों की अव्यवस्था के लिए उपभोक्ताओं को ही समूह बनाकर विरोध के लिए आगे आना होगा।

उन्होंने कहा कि व्यवस्था तंत्र या तो भ्रष्ट है या राजनैतिक प्रभाव से अपंग। कल के नौजवान को भ्रष्ट होने से बचाना ही होगा क्योंकि उससे ही हमें आशा है। अपनी शक्ति का सदुपयोग ही हमें इस समस्या से निजात दिलवाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशों की तरह ही यहां भी तुरन्त दंड की व्यवस्था होनी चाहिए।

थिंकर्स फोरम के संयोजक सुमन्त मिश्र का कहना था कि नगर का सुनियोजित विकास न होना यातायात अव्यवस्था का मुख्य कारण है। प्रशासन कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। महापालिका अपने दायित्वों का ठीक से पालन नहीं कर रही है। नागरिक भी नियमों का उल्लंघन करने में पीछे नहीं है। इन सब पहलुओं को भी देखना होगा।

परिचर्चा की अध्यक्षता करते हुए आर.आई.टी. के अर्थशास्त्री डा. विनायक राव ने कहा कि तकनीक, प्रबंध, अर्थ तथा सामाजिक व्यवस्था इस समस्या के मुख्य अंग हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होता क्योंकि अधिकारी पैसे की ओर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। अधिकारी समस्याओं को हल करने में रुचि नहीं लेते। उपभोक्ताओं को ही संघर्ष कर समाज में जागरूकता पैदा करनी होगी। परिचर्चा में डा. पूर्णिमा तिवारी, डा. सुन्दर लाल वर्मा, बृजेश सिंह एडवोकेट, शंकर प्रताप सिंह, रवि कुमार तिवारी आदि ने अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम संयोजक विपिन बिहारी मिश्र ने आभार व्यक्त किया। संचालन उपभोक्ता परिषद के निदेशक ध्रुव कुमार शुक्ल ने किया।

यातायात व्यवस्था पर विचार गोष्ठी का आयोजन

स्वतंत्र भारत 28-2-94

स्वतंत्र भारत संवाददाता

कानपुर, २७ फरवरी। उपभोक्ता परिषद की ओर से आज मिश्रा मार्केट, सीसामऊ बाजार में 'यातायात व्यवस्था' समस्याएं और सुझाव' विषय पर एक गोष्ठी आयोजन किया गया।

गोष्ठी में महापालिका के यातायात सेल के अधिशासी अभियंता प्रदीप तिवारी ने कहा कि सड़क, यात्री और फुटपाथ तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं, किंतु आज फुटपाथ पर लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए हैं। टैम्पो भार ढोने के लिए अधिकृत है किंतु इससे सवारियां ढोई जा रही हैं। सड़क आज स्वामित्वहीन हो गयी है और जो जैसा चाहता है, सड़क पर स्थाई या अस्थाई अतिक्रमण कर लेता है। इससे निपटने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक होना पड़ेगा।

डा. पूर्णिमा तिवारी ने नगर बसों को यातायात समस्या का एक कारण बताया और कहा कि गोविंद नगर पुल न जाने कब से खराब है किंतु मरम्मत करके काम चला लिया गया। डा. सुंदरलाल वर्मा ने सीसामऊ बाजार के अतिक्रमण पर चिंता जताई। अधिवक्ता बृजेश सिंह ने आवारा पशुओं की यातायात की सबसे बड़ी समस्या बताया और कहा कि वाहनों का तो पुलिस चालान कर देती है किंतु आवारा जानवरों को कोई नहीं छेड़ता।

सहायक सूचना निदेशक रवि तिवारी ने यातायात व्यवस्था में बढ़ती हुई आबादी को दोषी माना और कहा कि उपभोक्ताओं को खुद सुधरना पड़ेगा, तभी कोई हल निकलेगा।

आई.आई.टी. के वैज्ञानिक डा.विनायक ने आरोप लगाया कि कभी यहां योजनाबद्ध ढंग से यातायात सुधार अभियान नहीं चलाया गया। अधिकारी सिर्फ कानपुर में पैसा बटोरने में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को जागरूक करने के साथ साथ अधिकारियों को भी सजग किया जाना चाहिए।

गोष्ठी में ध्रुवकुमार शुक्ला, विपिन बिहारी मिश्रा, शंकर प्रताप सिंह ने भी अपने विचार प्रकट किए।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपभोक्त आन्दोलन की आवश्यकता

स्वतंत्र भारत 17.1.94

स्वतंत्र भारत संवाददाता

कानपुर, १६ जनवरी। उपभोक्त परिषद ने उपभोक्तओं की बहुआयामी समस्याओं पर होटल राजमहल में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में अर्थशास्त्री डा. विनायक रथ ने कहा कि उपभोक्त आंदोलन की सक्रियता केवल शहरी क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवश्यक है।

उन्होंने कहाकि कानपुर के लोग अनेक सामाजिक विसंगतियों के होते हुए भी मौन रहते हैं। श्री रथ ने स्वयंसेवी संस्थाओं को सक्रिय भूमिका निर्वाह करने का आस्वान किया।

संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए श्रम कानून सलाहकार बाल गोविन्द अग्रवाल ने कहा कि आज सामान्य श्रमिकों को उन उपभोक्त कानूनों की जानकारी नहीं है, जिनके जरिए उन्हें अनेक लाभ मिल सकते हैं। डा. बी.एन. सिंह ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ रही उपभोक्तवादी संस्कृति के कारण शिक्षा संस्कार विहीन होती जा रही है।

उनका कहना था कि आज इस बात की आवश्यकता है कि शिक्षा के मूलधर्म और गुण संस्कार को बनाए रखा जाए। डा. यतीन्द्र तिवा ने कहा कि उपभोक्त आंदोलन को आज आंदोल नहीं, उसे समाज सुधार आंदोलन के रूप चलाना ही उपभोक्त आंदोलन की सार्थकता होग

नरेश कुमार वर्मा ने कहा कि डंकल प्रस्त के लागू हो जाने से सामान्य नागरिकों पर ब विपरीत प्रभाव पड़ेंगे। वस्तुओं के पेटेंट हो जा पर इसी देश के निर्मित वस्तुओं पर यहां तक कि वनस्पतियों व उनके उपयोग और उपभोग प नागरिकों का अधिकार नहीं रह जाएगा। यह ए तरह से आर्थिक गुलामी होगी।

संगोष्ठी में बृजेश सिंह ने कहा कि कानपु के चिकित्सकों में यह सबसे बड़ी कमी है कि वे मरीजों की सही जांच नहीं करते, उन्हें दौड़ाते हैं चिकित्सकों की यह लापरवाही केवल इसीलिए है कि उनके नर्सिंग होम चलें। आज ऐसे डाक्टरों के खिलाफ उपभोक्त संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। संगोष्ठी के संयोजक ध्रुव कुमार शुक्ला ने कार्यक्रम का संचालन किया और उपभोक्त परिषद के उप निदेशक पी.के. जैकब आए हुए लोगों के प्रति आभार प्रकट किया।

17.01.94

उपभोक्ताओं के हित के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आएं

(अमर उजाला ब्यूरो)

कानपुर, १६ जनवरी। आई.आई.टी. के अर्थशास्त्री डा. विनायक रथ ने आज शहर की तमाम समाजसेवी संगठनों का आह्वान किया कि वे उपभोक्ताओं के हित के लिए सक्रिय भागीदारी निभाएं। श्री रथ उपभोक्ता परिषद की ओर से होटल राजमहल में आयोजित एक बहुआयामी गोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे।

श्री रथ ने कहा कि उपभोक्ताओं के हित के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। उपभोक्ता आंदोलन की शहरी क्षेत्रों से ज्यादा देहाती क्षेत्रों में आवश्यकता है। देहाती क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य समेत तमाम अन्य समस्याएं उपभोक्ताओं की हैं। उनकी तरह-तरह से शोषण किया जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि स्वयंसेवी संस्थाएं उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें।

संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए श्रम कानून सलाहकार बाल गोविन्द अग्रवाल ने श्रमिक उपभोक्ताओं की समस्याओं पर प्रकाश डाला। श्री अग्रवाल का कहना था कि आज सामान्य श्रमिकों को उन उपभोक्ता कानूनों की जानकारी ही नहीं है जिसके माध्यम से उन्हें तमाम लाभ मिल सकते हैं।

बी.एन. सिंह ने शिक्षा क्षेत्र की उन विसंगतियों की ओर इशारा किया जिनके चलते शिक्षा में उपभोक्तावादी संस्कृति पनपती जा रही है।

श्री सिंह ने कहा कि इसके प्रभाव से आज हमारी शिक्षा संस्कार विहीन होती जा रही है। उन्होंने शिक्षा के मूल धर्म, गुण और संस्कारों को बचाये रखने की जरूरत बतायी।

अर्मापुर डिग्री कालेज के प्राचार्य डा. यतीन्द्र तिवारी ने कहा कि उपभोक्ता आंदोलन को मात्र आंदोलन के रूप में नहीं वरन उसे समाज सुधार आंदोलन की तरह से चलाया जाना चाहिए। गोष्ठी में बृजेश सिंह एडवोकेट ने उपभोक्ता अधिनियम तथा उसमें किये गये संशोधनों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि डाक्टर मरीजों की सही तरीके से जांच करने में लापरवाही बरतें तो उनके खिलाफ श्री उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

उपभोक्ता आंदोलनको समाज सुधारके रूपमें चलाया जाय

उ. आज" 16-1-94

कानपुर, १६ जनवरी। उपभोक्ता परिषद के तत्वाधान में उपभोक्ताओं की बहु आयामी समस्याओं पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि डा. विनायक रथ अर्थशास्त्री आई. आई. टी. कानपुर के थे। उन्होंने कहाकि कि उपभोक्ता आन्दोलन की सक्रियता केवल शहरी क्षेत्रोंमें ही नहीं आवश्यक है वरन ग्रामीण क्षेत्रोंमें इस आन्दोलन को सक्रिय बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहाकि कानपुर के लोग कैसे हैं जो अनेक सामाजिक विसंगतियोंके होते हुये भी मौन साधे रहते हैं। उन्होंने स्वयं सेवी संस्थाओं को सक्रिय भूमिका निर्वाह करने का आवाहन किया। संगोष्ठी की अध्यक्षता वी. पी. दीक्षित ने की।

संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुये श्री बाल गोविन्द जी अग्रवाल, श्रीम कानून सलाहकार ने इस अवसर पर श्रमिकों की उपभोक्ता समस्याओं का उल्लेख करते हुये कहाकि आज सामान्य श्रमिकों को उन उपभोक्ता कानूनों को जानकारी नहीं है जिसके द्वारा उन्हें अनेक लाभ मिल सकते हैं। शिक्षा क्षेत्रमें व्याप्त अनेक विसंगतियों का उल्लेख करते हुये डा. वी. एन. सिंह ने कहाकि शिक्षा के क्षेत्रमें बढ़ रही उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण शिक्षा संस्कार विहीन होती जा रही है आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा के मूल धर्म और गुण संस्कार को बनाये रखा जाये। आज उपभोक्ता आन्दोलन की अत्यन्त निर्वल आय वर्ग के नागरिकों में सक्रिय करने की आवश्यकता पर बल देते हुये डा. यतीन्द्र तिवारी ने कहाकि उपभोक्ता आन्दोलन को आज आन्दोलन नहीं उसे समाजसुधार आन्दोलन के रुप में चलाना ही उपभोक्ता आन्दोलन की सार्थकता होगी।

उपभोक्ता परिषद के उपनिदेशक श्री पी. के. जैकप ने धन्यवाद किया। संयोजक तथा संचालन श्री ध्रुवकुमार शुक्ला ने किया।

उपभोक्ता सडकों पर चलने के अधिकार के लिये संघर्ष करें

दैनिक जागरण 28-2-94

(संवाददाता)

कानपुर, रविवार। महानगर की सड़कों पर अव्यवस्थित यातायात के लिये उपभोक्ताओं को एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिये, सड़कों पर चलना उनका मौलिक अधिकार है किन्तु अतिक्रमण के कारण उपभोक्ता इस अधिकार से वंचित हो रहे हैं।

उपरोक्त विचार आज यहां उपभोक्ता परिषद द्वारा यातायात व्यवस्था समस्यायें एवं सुझाव, विषय पर आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने व्यक्त किये।

संगोष्ठी की शुरुआत करते हुये नगर महापालिका (ट्रैफिक सेल) के अधिशासी अभियंता प्रदीप तिवारी ने कहा कि महापालिका द्वारा फुटपाथ के ऊपर दुकानों के लिये जगह का एलाटमेंट उसके सदुपयोग के लिये किया गया था किन्तु आज वही दुरुपयोग में परिणत हो गया है उन्होंने कहा कि टेम्पो तो गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिये बना था, यात्रियों के लिये नहीं। उन्होंने कहा कि अभियान्त्रिकी, शिक्षा एवं अतिक्रमण इस समस्या के तीन पहलू हैं। सड़कें आज स्वामित्वहीन हो गयी हैं जो जहां पैसा चाहे उपयोग कर रहा है लेकिन उनके लिये दंड की व्यवस्था नहीं है, सड़को के साथ खुले आम अनाचार हो रहा है। सड़कों के उपभोक्ताओं को सड़क पर चलने का हक हर हाल मे मिलना चाहिये।

उन्होंने नेताओं पर भी प्रहार करते हुए कहाकि वह अतिक्रमण नहीं हटने देते सभासदों ने भी अपनी मर्जी से कई गलत काम करवाये जिन्हें नहीं होना चाहिए था।

आई. आई. टी. के प्रोफेसर अर्थशास्त्री डा. विनायक रथ ने कहाकि इस समस्या के प्रमुख अंग तकनीकी, प्रबंधकीय, वित्तीय तथा सामाजिक है। उन्होंने कहाकि यातायात सुधार के लिए योजनायें तो बनी लेकिन उनका काम नहीं हुआ क्योंकि हर आने वाले अधिकारी का ध्यान धन पैदा करने पर रहा है। अधिकारी समस्याओं के हल में मन नहीं रखते।

डा. रथ ने कहाकि उपभोक्ता संगठनों को इस मामले में पहल करनी चाहिए।

संगोष्ठी का संचालन उपभोक्ता परिषद के निदेशक ध्रुव कुमार शुक्ला तथा आभार कार्यक्रम संयोजक विपिन बिहारी मिश्र ने किया। संगोष्ठी में डा. वी. एन. मित्र, अमीनुद्दीन अहमद, सुशील मिश्रा, डा. पूर्णिमा तिवारी, ब्रजेश सिंह, डा. सुन्दरलाल वर्मा, शंकर प्रताप सिंह आदि थे।

Discussion on traffic management held

पायनियर 28-2-94

Staff Reporter

Kanpur

ROADS IN the city are ownerless, for anyone can set up his shop on them and still go unpunished.

This was stated by Mr Pradip Tiwari, executive engineer (traffic cell) of Nagar Mahapalika while speaking at a seminar on 'City Traffic Management-Problems and Suggestions' organised by Upbhokta Parishad in Misra Market at Sisamau on Sunday.

Mr Tiwari, while talking of traffic, regretted that the intention of the Mahapalika by allotting space over the footpaths for their better utility had resulted in their misuse. The tempos which were meant for transport of goods were carrying passengers. He said that the user of the road must get his right.

Mr Ravi Kumar Tiwari, Asstt Director, Information said that the population explosion was the main contributing factor of the traffic problem in the city.

Dr Vinayak Rath, the IIT economist who presided over the seminar opined that technical, managerial, financial and social were the pivotal parts of the problem. The plan was not implemented because the incoming official was basically concerned with money-spinning.

अमर उजाला 28.1.96

महानगर में आज

- ग्रामीण उपभोक्ता प्रशिक्षण शिविर पंचायत भवन हरबसपुर, विधनू ब्लाक में पूर्वाह्न ११ बजे से।

दैनिक जागरण 2...

आज के व...

-कानपुर नगर तहसील के उपभोक्ता प्रशिक्षण शिविर विधनू हरबसपुर में पूर्वान्ह ११ बजे।

राष्ट्रीय सहारा 30.1.96

ग्रामीणों को उपभोक्ता संरक्षण की जानकारी दी

कानपुर, 29 जनवरी। साक्षरता के अभाव में ग्रामीण उपभोक्ताओं तक अधिनियमों की जानकारी नहीं पहुंच पाती है। इस कमी से ग्रामीण उपभोक्ताओं का खूब शोषण होता है।

ये बात जिला एवं सत्र न्यायाधीश कानपुर नगर बी.के. सरकार ने विधनू ब्लाक के पंचायत भवन में ग्रामीणों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जानकारी देते हुये कही। पंचायत भवन में उपभोक्ता परिषद ने प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था।

श्री सरकार ने बताया कि उपभोक्ता आन्दोलन इस शताब्दी के छठे दशक में पश्चिमी देशों द्वारा चालू किया। भारत जैसे विकासशील देश में भी उपभोक्ता संरक्षण के कानून बनाये गये।

श्री सरकार ने इस मौके पर परिषद द्वारा छपाये गये प्रोफार्मा कलेन्डर का वितरण कर बताया कि पांच लाख रुपये तक के माल एवं सेवाओं के हजनि की शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में की जा सकती है। ये प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थित न्यायिक संस्था है। कानपुर में ये न्यायालय रेन्ट कन्ट्रोल दफ्तर पर सप्ताह में तीन दिन बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को लगाया जाता है।

इस मौके पर उपभोक्ता परिषद के निदेशक श्री ध्रुव कुमार शुक्ला ने बताया कि ये अधिनियम निजी सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रों पर प्रभावी है जहां मूल्य लेकर वस्तु अथवा सेवाओं की बिक्री की जाती है।

शिविर में आई.आई.टी. के प्रोफेसर डाक्टर विनायक रथ जी खेती के रिकार्ड में होने वाली गड़बड़ियों की विस्तार से चर्चा की। इसी तरह बृजेश सिंह ने बताया कि सिंचाई, विद्युत, खेती के रिकार्ड में गड़वड़ी एवं शिक्षा के मामलों को फोरम की परिधि में आने का जिक्र करते हुए प्रशिक्षण दिया।

उक्त शिविर की अध्यक्षता श्रीमती जगदीश कौर ने की। सर्व श्री यतीन्द्र तिवारी प्राचार्य अर्मापुर डिग्री कालेज, राजेन्द्र श्रीवास्तव मंत्री भारत सेवक समाज, रामेन्द्र तिवारी, श्याम लाल तिवारी, रवीन्द्र तिवारी, राम आसरे शुक्ल, सीता राम वाजपेयी, जगत प्रकाश द्विवेदी, राघवेन्द्र सिंह आदि ने भी विचार रखे। संचालन परिषद निदेशक ध्रुव कुमार शुक्ल ने किया।

(४) दैनिक जागरण, कानपुर, ३० जनवरी, १९९६

कानपुर समाचार

अधिनियमों की जानकारी न होने से उपभोक्ताओं का शोषण

(प्रतिनिधि)

कानपुर, सोमवार। उपभोक्ता परिषद के तत्वावधान में आयोजित ग्रामीण उपभोक्ता प्रशिक्षण शिविर में जिला जज व सत्र न्यायाधीश वी. के. सरकार ने कहा कि ग्रामीण उपभोक्ताओं को अधिनियमों की जानकारी न होने के कारण शोषण हो रहा है।

पंचायत भवन, हरबसपुर विधनू ब्लाक में तहसील के उपभोक्ताओं के शिविर, कार्यशाला, उपभोक्ता परिषद के तत्वावधान में श्री सरकार ने कहा कि उपभोक्ता आंदोलन इस शती के ६वें दशक में पश्चिमी देशों में प्रारंभ हुआ था। भारत जैसे विकासशील एवं ग्रामीण बाहुल्य आबादी वाले देश में पहले कानून बने आंदोलन बाद में शुरू हुआ फिर भी साक्षरता के अभाव में ग्रामीण उपभोक्ताओं को अधिनियमों की जानकारी न होने के कारण शोषण की पराकाष्ठा हैं। श्री सरकार ने उपभोक्ता फोरमों में वाद प्रस्तुत करने तथा प्रमुख निर्णयों की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने उपभोक्ता परिषद की ग्राम स्तर तक इकाई बनाने की बात कही।

डा. विनायक रथ अर्थ शास्त्री आई. आई. टी. ने गांवों में अधिक स्कूलं की व्यवस्था एवं खेती के रिकार्डों में होने वाली गड़बड़ियों की विस्तार से चर्चा करते हुए इसके लिए आंदोलन छेड़ने का आह्वान किया। उपभोक्ता परिषद द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, नगर के पते सहित बनी टीन की प्लेटों का लोकार्पण डा. रथ ने किया।

बृजेश सिंह एडवोकेट ने बताया कि वस्तु व सेवा के एवज में चूंकि उसका मूल्य आप चुकाते हैं अतः आप सब उपभोक्ता हैं उन्होंने सिंचाई, बिजली, खेती रिकार्ड में गड़बड़ी शिक्षा आदि के फोरमों की परिधि में आने का जिक्र करते हुए स्टेट कमीशन एवं नेशनल आयोग के महत्वपूर्ण ग्रामीण उपभोक्ताओं के फैसलों एवं उनके क्रियान्वयन की विस्तार से चर्चा की।

राजेंद्र श्रीवास्तव मंत्री, भारत सेवक ने उपभोक्ताओं से संबंधित बने प्रमुख अधिनियमों की प्रमुख बातों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने की मांग की। डा. यतींद्र तिवारी प्राचार्य अर्मापुर पी. जी. कालेज, ने एक्सपायरी डेट के बाद की दवाओं के बिकने से अनेक की मृत्यु तक होने की अनेक घटनाओं का जिक्र करते हुए व्यापारी के रातों रात धनवान बनने की प्रवृत्ति की निंदा की।

श्रीमती जगदीश कौर सदस्या केंद्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड ने अध्यक्षता करते हुए महिलाओं के अधिक शोषण व उनके घर के बाहर निकल आने का आह्वान किया तथा उपभोक्ता परिषद की स्मारिका का लोकार्पण भी किया। ध्रुवकुमार, निदेशक उपभोक्ता परिषद ने संचालन किया।

...उपभोक्ता परिषद की ग्राम स्तर तक इकाइयां गठित की जाय ताकि ग्रामीणों को भी इसका लाभ मिल सके। अन्य वक्ताओं ने कहा कि उपभोक्ताओं से सम्बन्धित बने अधिनियमों की प्रमुख बातों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिए तभी लोगों में तभी जागरूकता लायी जा सकती है।

शिविर में मुख्य रूप से आई.आई.टी. के अर्थशास्त्री डा.विनायक रथ, अधिवक्ता बृजेश सिंह, डा.यतीन्द्र तिवारी, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की सदस्य जगदीश कौर ध्रुवकुमार शुक्ल आदि लोगों ने विचार व्यक्त किये।

अमर... 29...

"Dainik Jagaran", September 1, 1997

कानून व्यवस्था, पुलिस एवं जनता का पारस्परिक सहयोग गोष्ठी

अपराधियों की गोपनीय ढंग से सूचना दें व फुटपाथ खाली करें

❑पुलिस की जर्जर व्यवस्था ❑ टेम्पो में महिलाओं से अभद्रता ❑ सिपाही व दरोगा का व्यवहार ठीक नहीं ❑मनो प्रदूषण विकट समस्या

निज संवाददाता

कानपुर, रविवार। पुलिस महानिरीक्षक डी.एन. सामल ने जनता से अपराधियों की गोपनीय ढंग से सूचना देने तथा फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने का आग्रह किया है। उन्होंने पुलिस के लिये आधुनिक साधन व प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया तथा कहा कि पुलिस जन संसाधनों की कमी के बावजूद श्रेष्ठ बनें।

श्री सामल आज लाजपत भवन में कानून व्यवस्था, पुलिस एवं जनता का पारस्परिक सहयोग गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यातायात समस्या को मुख्य बताया तथा कहा कि कल उन्होंने पैदल चलकर देखा कि लोगों ने फुटपाथ घेर रखा है तथा उन्हें किराये तक पर उठा रखा है। अतिक्रमण से सबसे अधिक व्यापारियों को ही दिक्कतें होती हैं। उन्होंने बताया कि गोपनीय सूचनाओं के लिये एस.पी. स्तर तक सेल बनाये गये। उसकी समिति समीक्षा करके आवश्यक कार्रवाई करेगी। ऐसी व्यवस्था की जायेगी ताकि अधिकारियों के हटने पर भी कार्य चलता रहे। उन्होंने स्वीकार किया कि पुलिस अपेक्षित कार्य नहीं कर रही है तथा उसका आचरण भी अपेक्षित नहीं है। उन्होंने इसमें सुधार कराने का वादा किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक बुराइयों से पुलिस जन अछूते नहीं है। विशेष प्रशिक्षण से इसे दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि, राजनीतिक व आर्थिक कारणों, मूल्यों में गिरावट, परिवार टूटने आदि से पुलिस का कार्य क्षेत्र बढ़ा है तथा उग्रवाद, अपराध के नये-नये ढंगों, सांप्रदायिक व जातिवाद संघर्षों का मुकाबला करना कठिना हो रहा है।

पुलिस उप महानिरीक्षक होशियार सिंह बल्वारिया ने न्यायिक व प्रशासनिक व्यवस्था के पुनर्गठन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान जर्जर व्यवस्था में सुरक्षा कर पाना मुश्किल हो गया है। 20-20 साल पुराने 50 हजार मुकदमें विचाराधीन हैं। न्याय में विलंब व 5-6 प्रतिशत अभियुक्तों को दंड मिलने से माफिया पनप रहे हैं। पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिये 1977 में धर्मवीर आयोग बना, किन्तु आज तक अनुशंसाओं को लागू नहीं किया गया। विवेचना की गुणवत्ता में गिरावट आयी है। इसमें वैज्ञानिक संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होना चाहिये। विवेचना व कानून व्यवस्था के लिये अलग-अलग व्यवस्थायें होनी चाहिये।

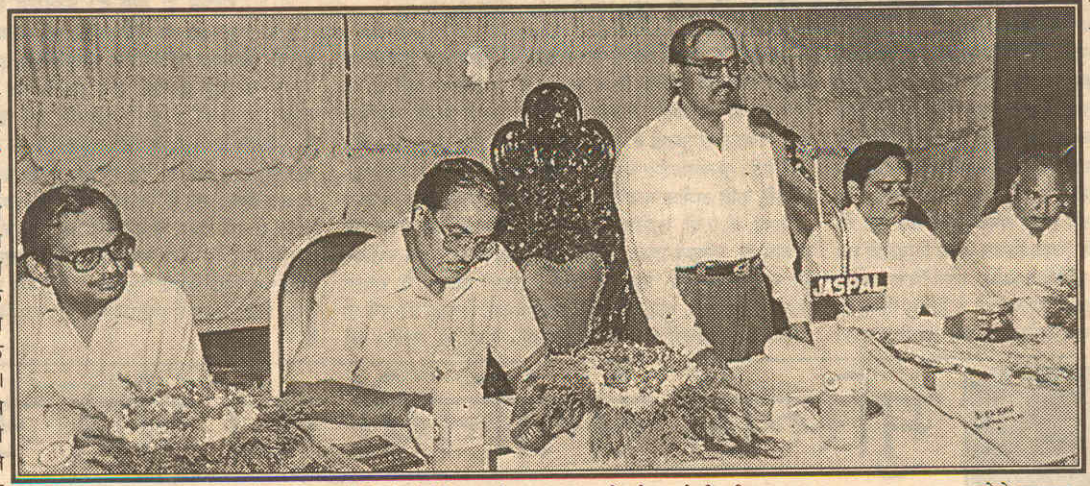

लाजपत भवन में आयोजित पुलिस एवं जनता गोष्ठी को संबोधित करते हुए कानपुर जोन के आई.जी. डी.एन.सामल। फोटो:जागरण

पूर्व जिलाधिकारी रामशरण श्रीवास्तव ने नगर की आबादी के संप्रदाय व जाति में बंटने को खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि सिपाही व दरोगा का जनता के साथ व्यवहार ठीक नहीं रहता है। नियमों व अधिनियमों में पूर्ण परिवर्तन किया जाय। आई.आई.टी. के प्रो. विनायक रथ ने जन समस्याओं का कारण विभागों में समन्वय का अभाव बताया। मार्ग प्रकाश न होने से अधिकांश दुर्घटनायें रात को होती हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता अर्जुन सिंह चौहान ने बोलने की स्वतंत्रता, स्रोत न बताने आदि अधिकारों का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस के लिये अनिवार्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति की सूचना उसके निकट संबंधी को दे। पी.पी.एन. के पूर्व प्राचार्य एन.के. सक्सेना ने कहा कि पुलिस पर दबाव, तनाव व राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है। अपेक्षित उपलब्धियां न मिलने से समस्यायें पनपती हैं। प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष एस.एच. नकवी ने प्रेस की विवशताओं का जिक्र किया। अर्मापुर डिग्री कालेज के प्राचार्य डा. यतीन्द्र तिवारी ने कहा कि सामाजिक प्रतिरोध व चेतना में कमी से समस्याएं जटिल हुईं। एस.पी. ट्रैफिक अखिलेश्वर तोमर ने थाने में सहयोग करने, विकास मंडप के राकेश बाजपेयी ने जनता पर नियम न थोपने, आजाद नगर के प्रताप नारायण अग्रवाल ने थानों में व्यवहार कुशल अधिकारी नियुक्त करने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानवती आर्या ने मनो प्रदूषण दूर करने के लिये टेम्पो बसों में भौड़े गानों के टेप बजाने पर प्रतिबंध, कवि कमल मुसद्दी ने शराब ठेके रात 10 बजे के बाद न खुलने देने, डी.जी. की प्रवक्ता बीना शर्मा ने महिला कालेजों के पास महिला पुलिस तैनात करने, रिपब्लिकन पार्टी के हीरालाल जैसवार ने थानों में गरीबों की सुनने, गीता प्रेस के जुगुल बिहारी गुप्त ने जनता से पुलिस का भय दूर करने, विद्या मंदिर के सचिव डा. आई.सी. गुप्त ने महिला विद्यालयों के बाहर छेड़छाड़ रोकने के लिये सादी वर्दी में पुलिस तैनात करने, भारत विकास परिषद दक्षिण के मंत्री प्रेम प्रकाश मिश्र ने टेम्पो प्रदूषण रोकने व पुन: अतिक्रमण न लगने देने, महिला नेता रोशनी रोंगटी ने टेम्पो में महिलाओं के साथ अभद्रता रोकने, भारत सेवक समाज के गुरुचरन वासू ने पुलिस गोष्ठियों में सज्जनों को बुलाने, एस.के. चौहान ने शांति मिश्र ने पुलिस की आवास, भोजन की दिक्कतों का जिक्र किया तथा कहा कि पुलिस व जनता के बीच की दूरी मानसिकता बन गयी है। बेकरी एसोसियेशन के अध्यक्ष चन्दूलाल आडवाणी ने लाठी का दुरुपयोग न करने , कर्मचारी नेता नईमुद्दीन सिद्दीकी ने जनता के बीच जाकर समस्याएं सुनने, आर्डिनेंस कर्मचारी राम अनुज समितियों में अच्छी छवि वालों को स्थान देने के सुझाव दिये।

शहर पुलिस अधीक्षक आर.के.एस. राठौर के संचालन में गोष्ठी में अवकाश प्राप्त पुलिस उपाधीक्षक सुरेन्द्र पाल शर्मा ने कहा कि थानों में पी.आर.ओ. नियुक्त हों व सज्जनों की बैठक बुलाई जाय। अवकाश प्राप्त पुलिस उपाधीक्षक आर.एन. शर्मा ने कहा कि थाने लावारिस रहते हैं। थानों में थानाध्यक्षों के रहने की व्यवस्था की जाय। अवकाश प्राप्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम अग्रवाल ने हर माह नागरिकों की मीटिंग करने को कहा। पुलिस उपाधीक्षक (नजीराबाद) रामलाल वर्मा ने कहा कि दुकानदार पुन: अतिक्रमण न होने दें तथा जनता टेम्पो में 6 सवारी के बाद न बैठे। नजीराबाद इंस्पेक्टर आर.पी. सिंह ने अपराधों की गुप्त सूचना देने पर बल दिया। सीसामऊ के रामेश्वर यादव ने कहा कि जब चौकी इंचार्ज सरेआम जेल से छूटे लोफड़ों से थाने व उसके बाहर बात करते हैं तो जनता का मनोबल टूटता है। ट्रांसपोर्ट एसोसियेशन के मंत्री श्याम कुमार गुप्त ने कहा कि पुलिस थानों व चौकियों के माध्यम से अतिक्रमण न करें। विकास मंडप के आर.के. बाजपेयी ने जनता मोबाइल फोन का उपयोग व्यवसाय के साथ अपराधों की सूचना देने में भी करे। हृदय कुमार गुप्त व अयोध्या प्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज न किये जाने की शिकायत की। महिला मंच की नेता नीलम चतुर्वेदी ने कहा कि पुलिस के गालियां बकने पर रोक लगायी जाय। 80 प्रतिशत गालियां महिलाओं, 10 प्रतिशत हरिजनों व 10 प्रतिशत जानवरों से संबंधित होती हैं।

गुरु सिंह सभा के सचिव महेन्द्र सिंह विन्द्रा ने पुलिस की तत्परता पर बल दिया। सर्राफा कमेटी के सचिव रमेश चन्द्र दीक्षित ने कहा कि शक के आधार पर पुलिस का उत्पीड़न बंद हो। पी. रोड के व्यापारी नेता महेश मेघानी ने कहा कि सम्मन तामील न करके गैर जमानती वारेंटों की प्रतीक्षा होती है और शोषण किया जाता है।

जागरण प्रश्न प्रहर

आम बजट पर प्रश्न पूछिए

राकेश गर्ग, अध्यक्ष
आयकर बार एसोसियेशन
12 बजे से 1 बजे तक

डॉ. बिनायक रथ
प्रोफेसर–अर्थशास्त्र,
आई.आई.टी.
1 बजे से 2 बजे तक

पी. के. भार्गव
कार्यवाहक अध्यक्ष(नार्दर्न रीजन)
भारतीय उद्योग परिसंघ
2 बजे से 3 बजे तक

230625 पर पहली मार्च को

दैनिक जागरण, कानपुर, 2 मार्च 2001

सामाजिक न्याय पीछे, कृषि निवेश 2.6 फीसदी

जागरण प्रश्न प्रहर में आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बिनायक रथ ने कहा बजट विकासोन्मुखी हो सकता है लेकिन ग्रामीणोन्मुखी कतई नहीं है क्योंकि परिवहन, संचार व उर्जा में लगभग 60 प्रतिशत निवेश के मुकाबले कृषि सम्बंधित क्षेत्र को सिर्फ 2.6 प्रतिशत दिया गया है। सामाजिक न्याय पीछे छोड़ देने से गरीब का भला नहीं होगा।

*बजट से किसानों को लाभ मिलेगा -राम शंकर पाण्डेय, पड़नी

--किसान को लाभ नहीं मिलेगा, कृषि क्षेत्र में 97-98 में विकास दर 6.1, 98-99 में 7.7 प्रतिशत थी, किंतु इस वर्ष वृद्धि सिर्फ 0.9 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र में गिरावट को विकासशील करने के लिये जितनी लागत जरूरी थी नहीं दी गयी।

*पहली बार कृषि व कुटीर उद्योग का बजट कहना कितना सही है-विकास द्विवेदी, के. ब्लाक किदवई नगर, *कुटीर उद्योग को क्या लाभ मिलेगा- केशव, अवन्ती बाई इंटर कालेज, कड़री

--कृषि व ग्रामीण विकास पर पूरा ध्यान दिए बिना अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। यह बजट विकासोन्मुखी हो सकता है लेकिन ग्रामीणोन्मुखी नहीं है क्योंकि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की केन्द्रीय योजना में निवेश कम कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र में अन्तर बढ़ेगा।

*खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ाना, क्या गरीब का निवाला खींचना नहीं-अशरफ अली, एडवोकेट

--वित्त मंत्री ने कहा है कार्यकुशलता व सामाजिक न्याय साथ लेकर चलेंगे, किन्तु वास्तविक आवंटन में ये दोनों चीजें नहीं है। कार्यकुशलता आगे करके सामाजिक न्याय पीछे छोड़ दिया गया है। इस कारण गरीब आदमी को अधिक फायदा नहीं मिलेगा।

*बजट के बाद मुद्रा स्फीति की दर व महंगाई क्यों बढ़ती है-अनिल अवस्थी, किदवई नगर

--उद्योगपतियों को पता होता है कि बजट में दाम बढ़ेंगे, इसीलिए अर्थशास्त्र का नियम हो गया है कि बजट के बाद दाम बढ़ जाते हैं।

*भारत कृषि प्रधान देश किंतु किसी बजट में इसे तरजीह नहीं मिली-राजकिशोर तिवारी फजलगंज

* खेती में आयकर क्यों नहीं लगता-मनीराम अग्रवाल, उद्योग व्यापार मंडल

--कृषि के लिए बड़ी योजनाओं की बात भ्रम है। कृषि क्षेत्र का निवेश दूसरे क्षेत्र की अपेक्षा काफी कम है। इस साल के बजट में ऊर्जा के लिये 25.95 प्रतिशत, परिवहन 17.34 प्रतिशत, संचार में 15.59 प्रतिशत जा रहा है जबकि कृषि व संबंधित क्षेत्र के लिये सिर्फ 2.6 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। धनी कृषकों पर कर लगना चाहिए, किन्तु बिना मजबूत सरकार आए यह संभव नहीं है।

*1993 में मनमोहन सिंह द्वारा पेश बजट के बाद सभी बजटों में रेल किराया छोड़ अन्य मदों में वृद्धि हो रही है-दिलीप सिंह, श्री राम मित्र मंडल

--1993-94 की तुलना में इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों व गरीबों के लिए आवंटन कम हुआ है। इसी से गरीबों को फायदा नहीं हो रहा है।

*1991 से 2000 के दशक में देश में विकास के स्थान पर गरीबी बढ़ने का क्या कारण है-सत्येन्द्र द्विवेदी, सट्टी, शाहजहाँपुर, कानपुर देहात

--इस अवधि में गरीब और गरीब व अमीर अधिक अमीर हुए हैं। इस बजट से यह अंतर और बढ़ेगा। दरअसल सरकार ने सुधार अंतर्राष्ट्रीय व उद्योग हित देखकर निर्धारित किए हैं। सामाजिक न्याय के लिए पुनर्वितरण परध्यान नहीं दिया गया।

*सोने पर आयात शुल्क कम करने से विदेशी मुद्रा गैर उत्पादक कार्यों पर खर्च होगी-डॉ.जय प्रकाश साहू, आजाद नगर

--वर्तमान में विदेशी मुद्रा की स्थिति खराब नहीं है। अब हम स्वर्ण निर्यात भी कर सकते हैं। सरकार को उम्मीद है विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा।

*बजट मध्यम वर्ग के लिए कितना खराब है -विनोद निगम, चकेरी

--बजट मध्यम व उच्च वर्ग को ही फायदा पहुंचाएगा। निम्न मध्यम व गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। टीडीएस कम करना ठीक है। अल्प बचत में ब्याज दर घटाने के बाद ऋण की ब्याज दरें भी घटेंगी। इक्विटी व सामाजिक न्याय के आधार पर यह बजट अच्छा नहीं है।

*अगले दो वर्ष में 6000 करोड़ से अधिक का बजट घाटा और भारी विदेशी कर्ज का भुगतान कैसे होगा -संजीव तिवारी, किदवई नगर

--सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर ज्यादा निर्भर कर रही है। घरेलू स्त्रोतों से घाटा पूरा नहीं कर पाएंगे तो विश्व की विविध संस्थाओं से ऋण लेना होगा। सरकार ने सार्वजनिक इकाइयों के विनिवेश से 12 हजार करोड़ अर्जित कर 6 हजार करोड़ के बजट घाटे से उबरने की नीति बनाई है। विदेशी कर्ज के भुगतान के लिए दीर्घावधि समाधान चाहिए।

*सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चीनी के दाम बढ़ाना उचित है -श्याम पाण्डेय, पी.रोड

--उचित है। इससे किसान को लाभ मिलेगा।

* बजट से रोजगार बढ़ेगा-श्रीराम, दबौली

-- बेरोजगारी दूर करने के इंतजाम नहीं है।

*जनता से वसूले एक रुपए में ब्याज भुगतान तो होगा किन्तु कर्ज वापसी का प्रावधान नहीं है, इससे तो कर्ज बढ़ेगा-हर नारायण तिवारी, रावतपुर

--26 प्रतिशत ब्याज में जा रहा है। चाय, काफी में भारत का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटने से उत्पाद शुल्क में परिवर्तन हुआ है। सरकार को उम्मीद है इससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा।

*पं. नेहरू की सामाजिक, आर्थिक परिकल्पना क्यों सार्थक नहीं हुयी-कौशल किशोर, पी. रोड

--अर्थनीति में कमी नहीं रही, प्रशासनिक खामियों से उद्देश्य नहीं मिला। निजीकरण से भी सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता क्योंकि यह कार्यकुशलता के आधार पर ही फलीभूत होता है।

* कृषि उत्पादों पर आलू चिप्स निर्यात जैसी योजनाएं क्यों नहीं लागू होती-सुनील, मोतीमोहाल

--ऐसी योजनाओं से किसान को नहीं उद्यमी व निर्यातक को लाभ मिलता है।

*अर्थव्यवस्था पटरी पर कैसे आए -अनुराग तिवारी, विकास नगर

--विभिन्न क्षेत्रों में अधिक से अधिक पूंजी लगाने के साथ ही प्रशासनिक व न्यायिक सुधार आवश्यक है।

दैनिक जागरण, कानपुर 20 फरवरी 2001

क खतरे पर गड्ढा भरवाया

ी गयी थी। आज सुबह गड्ढे के दोनों तरफ की मिट्टी भरभरा कर अंदर ढहने से क्षेत्र में हल्ला मच या। विधायक राकेश सोनकर, सोम, कांग्रेस नेता कमल जायसवाल, सुबोध बाजपेई ने मांग की कि मिट्टी तुरंत भरायी जाये, अन्यथा जनता खुद भर

भन्नानापुरवा में फिर मिट्टी धसकने से हल्ला

ी। जल निगम गंगा प्रदूषण इकाई महाप्रबंधक र. देशपांडे, बैराज इकाई के अधिशासी राधेश्याम डिलवाल व अन्य अभियंता मौके पर पहुंचे। दाई स्थल के दोनों तरफ पानी का रिसाव व मिट्टी ी दशा देखकर अगल-बगल की इमारतें धसकने का खतरा माना गया। तुरंत मिट्टी से गड्ढा पाटने का निर्णय हुआ और प्रोजेक्ट इन्जीनियर एच. के कंसल ने अफीमकोठी से लोडर बुलवाया। श्री देशपांडे का कहना है कि अंगराज को काली सूची में डाला जाएगा। कांग्रेस के ज्ञानेन्द्र मिश्रा ने सहायक श्रमायुक्त से वार्ता करके मृतकों को कानूनन ढाई लाख रुपये मुआवजा दिलाने पर जोर दिया। लोकतांत्रिक कांग्रेस की कनक मिश्रा ने मुख्यमंत्री से दोषियों पर कार्रवाई व एक-एक लाख मुआवजा मांगा जबकि माकपा की सीमा कटियार ने भ्रष्ट इंजीनियरों को बर्खास्त करने की मांग की। भाजपा विधायक राकेश, अनूप अवस्थी ने कहा कि ठेकेदार अंगराज व दोषी अधिकारियों को सजा हुए बिना अपने क्षेत्र में काम नहीं होने देंगे, मुख्यमंत्री को सारे प्रकरण से अवगत करायेंगे।

कटे केबिलों से मजदूरों की जान खतरे में

संवाददाता

कानपुर, मंगलवार। नगर में जगह-जगह हो रही खुदाई के कारण कटे केबिलों से मजदूरों को करंट लगने व जान जाने का खतरा है। केस्को प्रबंध निदेशक विष्णु अवतार चतुर्वेदी ने आज इस बारे में शासन को पत्र लिखकर सचेत किया।

विशेष सचिव (नगर विकास) को लिखे पत्र में श्री चतुर्वेदी ने कहा है नगर में खुदाई के कारण केस्को के भूमिगत केबिल अनेक जगह कट गए हैं और फाल्ट हो चुका है। खुदाई वाले अधिकांश स्थलों पर हाईटेंशन लाइन का भूमिगत केबिल बिछा है, जिसमें कई हजार वोट का करंट बहता रहता है। मजदूर खुदाई में फावड़ा, कुल्हाड़ी आदि का प्रयोग करते हैं, इनसे केबिल कटने व करंट की चपेट में आकर जान जाने का खतरा है।

ठेके

कानपुर, ग
हुई छह गरीब
निगम के जि
ने कल ठेकेद

प्रथम दृष्ट
अभियंता एस
अंगराज के
किराये पर व
बंगाल दिख
कमल यादव
बनौधा, इटि
पहुंचकर का
महाना व वि
महाना का

ड़े गये

ों में दबिश देकर दस संदिग्ध बदमाशों को ड़ा इनमें कम से कम चार पूर्व में सनसनीखेज ों में प्रकाश में आ चुके हैं। बदमाशों से पूछताछ रही है। उधर स्पेशल आपरेशन ग्रुप मरे कंपनी के पास मारुति वैन समेत पकड़े गये तीनों कों से पूछताछ कर रहा है। ग्रुप ने तीन अन्य ों को भी हिरासत में लिया है, दो बदमाशों के सामने आये हैं। नये एस.पी.सिटी पंकज कुमार ाज रात कोतवाली में क्षेत्राधिकारियों, थाना रियों व चौकी इंचार्जों की बैठक में कोहना तथा र रोड लूट पर मुख्य रूप से चर्चा की। एस. टीम भावना के साथ वारदातों का खुलासा में जुटने को कहा। डी. आई. जी. दिलीप ही के निर्देश पर बिना नम्बर के वाहनों की धर-

जागरण प्रश्न प्रहर

आम बजट पर प्रश्न पूछिए

राकेश गर्ग, अध्यक्ष
आयकर बार एसोसियेशन
12 बजे से 1 बजे तक

डॉ. बिनायक रथ
प्रोफेसर-अर्थशास्त्र,
आई.आई.टी.
1 बजे से 2 बजे तक

पी. के. भार्गव
कार्यवाहक अध्यक्ष(नार्दर्न रीजन)
भारतीय उद्योग परिसंघ
2 बजे से 3 बजे तक

☎ 230625 पर पहली मार्च को

प्रध

रसूलाब
पुलिया के
विवाह सम
इसलिए प
हत्या क
अमर सिंह
ममेरी बहन
रोशनाई से
लगाए बैठे
मौजमपुर
के लिए र
स्थल पर
नम्बर यू.
देवी ने पू
ही हत्या

प्रदेश को चाहिये 'न्यूनतम वैज्ञानिक साक्षरता' वाली सरकार

शिक्षा संवाददाता, कानपुर

सोमवार

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के प्रोफेसरों की राय है कि प्रदेश की सरकार में मंत्रियों की संख्या चाहे भले ही अधिक हो परन्तु उनके विशेषाधिकार, खर्चे व मिलने वाली सुविधाएं कम की जानी चाहिये। प्रदेश को एक न्यूनतम वैज्ञानिक साक्षरता वाली सरकार चाहिये जो वैश्विक व राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रदेश का सम्यक विकास कर सके।

प्रोफेसरों ने कहा कि वे मतदान अवश्य करते हैं। देश के लोकतंत्र में कमजोरियां आई हैं तो उसकी अपनी विशेषताएं भी हैं। इसलिये सभी को मतदान करना ही चाहिये। मतदान न करने का अर्थ है लोकतंत्र की जड़ें कमजोर करना।

आईआईटी प्रबंध मंडल के सदस्य व अर्थशास्त्र के प्रोफेसर **डॉ. विनायक रथ** का कहना है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिये सचेतन व्यक्तियों के पक्ष में मतदान करना जरूरी है। ग्रामीण बहुल इस प्रदेश को ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने, शिक्षा स्वास्थ्य की दशा सुधारने वाली सरकार चाहिये।

प्रत्याशियों को चुनाव खर्च पार्टी के बजाय राज्य सरकार दे तो चुनाव में धनबल व बाहुबल के माध्यम से आने वाले अपराधियों को रोका जा सकता है। विज्ञान व तकनीक को यथेष्ट विकास क्रम जारी रखने के लिये सरकार को इंटर स्तर तक की विज्ञान शिक्षा के प्रति गम्भीर होना चाहिये।

आईआईटी प्रोफेसरों की राय

भौतिकी के प्रोफेसर **डॉ. हरीश चन्द्र वर्मा** कहते हैं कि चुनाव, शासन-प्रशासन और लोक जीवन में आई चरित्रहीनता की बीमारी का तात्कालिक इलाज न करके उसे जड़ से मिटाने की जरूरत है। इसके लिये जो समाज को चेतना देने वालों को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिये आगे आना होगा परन्तु अफसोस है कि वे खुद उस व्यवस्था का अंग बनते जा रहे हैं।

किसी भी सरकार में मंत्रियों की संख्या नहीं उनकी सुविधाएं कम करने की जरूरत है। उन्हें सामान्य विधायक से दस फीसदी से अधिक सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिये। आम आदमी, उद्योग, कृषि, कानून व्यवस्था आदि के प्रति संवेदनशील सरकार होनी चाहिये। अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक के काम में पारदर्शिता जरूरी है।

यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग के प्रोफेसर **डॉ. विजय कुमार जैन** कहते हैं कि सभी जानते हैं कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी कहां है? उस पर सीधे प्रहार करने की जरूरत है। इसके लिये कुछ और 'टी. एन. शेषन' चाहिये जो एकजुट हो कर चुनाव से भ्रष्टाचार व अपराधीकरण को दूर कर सकें।..30 प्रतिशत प्रतिनिधि ही सीधे चुनाव से लाये जायें शेष विशेषज्ञों को मनोनीत किया जाये। प्रतिनिधियों को पहले स्थानीय समस्याओं को हल करने का कम करना चाहिये।

भौतिक विज्ञान के **प्रो. डॉ. विजय ए. सिंह** का कहना है कि मतदान करना लोकतंत्र का एक हिस्सा है। सरकार व समाज के हर व्यक्ति में न्यूनतम वैज्ञानिक साक्षरता होनी चाहिये। कृषि प्रधान देश के किसी भी राज्य की सरकार को वैश्विक स्तर पर ऐसा सोच पैदा करना होगा जो हमारी फसलों को विदेशों में पेटेंट होने से बचा सके।

प्रदेश के उद्योग-व्यापार तथा विज्ञान व प्रौद्योगिकी विकास की गति को तेज करने वाली नीति नियामक सरकार होनी चाहिये।

नेशनल बिंड टनल के वरिष्ठ शोध अभियंता **डॉ. राजीव गुप्ता** की सलाह है कि पार्टियों को प्रत्याशी मुख्य चुनाव आयुक्त व मुख्य न्यायाधीश को सौंप देने चाहिये। उनकी समिति इन प्रत्याशियों के बारे में सम्पूर्ण जांच पड़ताल करने का अधिकार होना चाहिये। समिति जिनकी संस्तुति करे उन्हीं को चुनाव में लाया जाना चाहिये।

इससे नागनाथ-सांपनाथ में किसको चुनें की समस्या खत्म हो जायेगी।

Hindustan Times

'Building new power plants with present tariff not profitable'

HT Correspondent
Kanpur, December 30

BUILDING NEW power plants within the present average tariff is not profitable says Dr Joel Ruet an expert from Centre de Sciences Humaines from Delhi while speaking on the "Investment Profitability In Bridging the Power Gap in India" at the six day seminar on "Restructuring and Financing of Power Sector" at the Indian Institute of Technology (IIT) here he said. "Of course, the generation of new Plants is, according to the cost plus system to be paid at higher than average tariff would lead to a sixteen percent profitability", he added.

He said that the strategy of building new Plants required an investment of Rs 60,000 crores for an annual cash flow of rupees 2300 crores only. He suggested that instead of going for new Plant to ensure better Plant Load Factor (PLF) which required rupees 28000 crores, it would be wise to improve the PLF of the existing Power Plants. This would be a less expensive process, he suggested.

Professor V Ranganathan from Indian Institute of Management (IIM) stressed upon the need of tri-furcation of jurisdiction between Government, Regulator and the market for achieving perfect reforms in the power sector of the country

. He said at present the power sector in the country was controlled and managed by the State and the Central government with some private participation. But the emerging situation is that in the next few years power will be treated as an industry.

पैसे वाले लोग ज्यादा चुराते हैं बिजली -बागची

कार्यालय संवाददाता
कानपुर, 29 दिसंबर

दिल्ली विद्युत बोर्ड के पुलिस महानिरीक्षक (प्रवर्तन) देबाशीष बागची ने कहा कि गरीबों की अपेक्षा पैसे वाले और प्रभावशाली लोग बिजली की चोरी ज्यादा करते हैं। आईआईटी में आयोजित ऊर्जा क्षेत्र के पुनर्गठन, संबंधी कार्यशाला में शिरकत करने आए महानिरीक्षक ने पत्रकारों से बातचीत में अपनी बात के समर्थन में उदाहरण भी दिए।

उन्होंने कहा कि प्रवर्तन दल ने एक बार तीन हजार झुग्गी-झोपड़ियों में छापा मारा, तो वहां 18 किलोवाट बिजली चोरी होती पाई गई। इसके विपरीत अकेले दो गेस्ट हाउसों में 214 किलोवाट बिजली की चोरी हो रही थी। उन्होंने प्रभावशाली लोगों के धौंस के साथ बिजली चोरी के कई किस्से, सुनाए। महानिरीक्षक ने कहा कि जब उन्होंने 1998 में कार्यभार ग्रहण किया तो विभागीय अधिकारी लाइन लास को जोड़ कर बिजली बताते थे। इस प्रवृत्ति को खत्म कराया गया है। यही नहीं 1998 में जहां 160 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली होती थी और आज यह रकम 320 करोड़ रुपये है। इस दौरान 18 फीसदी बिजली की मांग भी बढ़ी है।

इससे पहले तीन तकनीकी सत्रों में भी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर बिनायक रथ ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर रोशनी डाली। उनके अलावा आईआईटी के ही डा. अनूप सिंह और ऊर्जा वित्त निगम के के.के. गोविल ने भी व्याख्यान दिए।

Dainik Jagran.
30Dec-2001

गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से बिजली संकट का समाधान

संवाददाता, कानपुर

शनिवार

बिजली संकट के समाधान के लिए हर स्तर पर गैरसरकारी संगठनों की व्यापक सहभागिता जरूरी है। आईआईटी में चल रही ऊर्जा क्षेत्र के वित्तीय व ढांचागत पुनर्गठन विषयक कार्यशाला को संबोधित करते हुए आईआईटी के अर्थशास्त्री प्रो.बिनायक रथ ने कहा कि गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से संकट के समाधान की पहल की जानी चाहिए।

प्रो.रथ ने कहा कि हर विकास परियोजना को निजी भूमि व सामान्य संपत्ति संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसमें जंगल, सड़क, नहरें आदि का अधिग्रहण कर उनका प्रयोग किया जाता है किन्तु अब अधिग्रहण में भी तमाम खामियाँ आ गयी हैं। पुनर्वास की दृष्टि से मुआवजे का भुगतान भी ठीक प्रकार से नहीं होता है। उन्होंने कहा कि नकद मुआवजे के लिए निर्धारित की जाने वाली दरें मूल आर्थिक नियमों व आधारों के विपरीत होती हैं। गैर सरकारी संगठनों की बढ़ती भूमिका के साथ न्याय पालिका, विश्व बैंक व परियोजना से जुड़े लोग संबंधित परियोजना से प्रभावित परिवारों के विरोध का भी सामना करते हैं।

प्रो.रथ ने कहा कि परियोजना लागत के साथ भूमि के रूप में भौतिक लागत, जल व वायु प्रदूषण तथा भूमिहीनता जनित सामाजिक व आर्थिक लागत भी सामने आते है। इसके अलावा बेघर, बेरोजगार व आय का समन्वय स्थापित न हो पाने जैसी समस्याओं का सामना भी समाज को करना पड़ता है। विकास करने वाले को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोगी एजेंसियों व पीड़ित पक्षों की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती का सामना भी करना पड़ता है। उन्होंने एक ऐसे स्वरूप को अपनाने पर बल दिया, जिसमें विकास व परियोजना से जुड़े सभी पक्षों की व्यापक भूमिका हो। उन्होंने कहा कि इसमें गैर सरकारी संगठनों को सकारात्मक भूमिका का निर्वाह करना होगा।

अभियंता के खिलाफ कार्रवाई

कानपुर, शनिवार: स्टाफ रिपोर्टर। कानपुर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अनीता भटनागर जैन ने भ्रष्टाचार में लिप्त भवन विभाग के सहायक अभियंता आर.के. जायसवाल की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि करके नियोजन विभाग में स्थानांतरित कर दिया। श्रीमती जैन ने बताया कि यह अभियंता बिना तकनीकी सलाह के फाइल पास कर देता था। पटकापुर का एक मामला उनके संज्ञान में लाया गया। घूम फिर कर यह फाइल मुख्य अभियंता के पास आ जाती थी।

SEPTEMBER 28 2003

HINDUSTAN TIMES

Water conservation stresses planning, people participation

HT Correspondent
Kanpur, September 26

IN ORDER to gain success in water conservation projects, all that is needed are the '3Ps', proper planning, political will and people's active participation.

This was stated by Professor of Economics Department, Indian Institute of Technology, Kanpur, Dr Binayak Rath, here on Friday. Rath, a specialist of cost-benefit analysis, environmental impact assessment and water resource management, was speaking during the inauguration of a two-day workshop on 'Overcoming water scarcity and quality constraints'.

The workshop started at St Mary's Convent School.

It is targeted at creating awareness on water conservation and how to save water resources for the next generation.

Students and teachers from more than 30 institutions of the city attended the workshop. It was organised by Eco Friends.

Principal of St Mary's Convent High School, Sister Smitha, highlighted the need for water in an individual's life during her welcome address. Dr Anil Dixit chaired the opening session which was devoted to the Ganga Action Plan (GAP).

Rakesh Jaiswal of Eco Friends presented the initial oration of the session. Jaiswal presented an overview of the GAP with special reference to issues and problems of Kanpur.

BP Shukla of the Central Pollution Control Board and Dr Padma S Vanker of Indian Institute of Technology, Kanpur gave a presentation on the impact of heavy metal pollution on the Ganga and consequential effects on public health.

Dr M Boswal of the Christ Church College, while chairing the second session, expressed concern on the issue of interlinking rivers. Water and energy expert Dr Sudhirendar Sharma highlighted the pitfalls of the project. Professor of Civil Engineering at Indian Institute of Technology, Kanpur Dr Bithin Dutta also talked about the lacunae in the project.

Students and teachers actively participated in the last session of the workshop.

The workshop was convened by PJ Thomas of St Mary's Convent High School.

HINDUSTAN

राजनीतिक जुड़ाव के बगैर पर्यावरण सवांरना मुश्किल

कानपुर (नि.सं.)। ईको फेंड्स ने कानपुर में जल की गुणवत्ता तथा अभाव विषय पर आयोजित कार्यशाला में वक्ताओं ने कहा कि जल प्रबंधन के लिए तीन पक्ष जरूरी हैं। योजना राजनीतिक और सरकारी इच्छा शक्ति के अलावा जनता का जुड़ाव किसी भी समाधान के लिए बेहद आवश्यक है।

सेंट मरीज कांवेंट में आयोजित कार्यशाला में तीस शिक्षकों और छात्रों के अलावा जल क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। आई.आई.टी. के डा. विनायक रथ ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि जल प्रबंधन के लिए सही योजना की आवश्यकता है इसके अलावा राजनीतिक और सरकारी इच्छा शक्ति भी जरूरी है। जब तक जनता किसी समस्या से नहीं जुड़ती तब तक समाधान संभव नहीं। डा. अनिल दीक्षित ने गंगा तथा गंगा कार्ययोजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। राकेश जायसवाल ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी अनेक जिम्मेदारियां हैं। बोर्ड के बीपी शुक्ला ने गंगा कार्य योजना की कमियों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी।

सिस्टर स्मिता, डा. एम. बोसवाल, डा. सुधिरेंदर शर्मा आदि ने पर्यावरण के संदर्भ में विचार व्यक्त किये। नदियों के जोड़ने की योजना में आ रही कठिनाइयों तथा लाभ का विश्लेषण किया। उन्होंने सामाजिक मूल्य तथा परियोजना की सफलता पर प्रश्नचिन्ह लगाया। आई.आई.टी. के डा. विपिन दत्ता ने आम जनता को परियोजना से जोड़ने का आह्वान किया। संचालन पीजी थामस ने किया।

AMAR UJALA

जीवन के लिए जरूरी है शुद्ध जल

सेंट मैरीज कांवेंट में हुई एक कार्यशाला में जल की गुणवत्ता पर रोशनी डाली गई। ईको फ्रैण्ड्स संस्था की इस कार्यशाला में जल, जीव और प्रकृति के बीच समन्वय बनाने की बात की गई। कार्यशाला में तीस स्कूल से आए छात्रों व विशेषज्ञों ने हिस्सेदारी की। कार्यशाला का उद्घाटन आई.आई.टी. में अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डा. विनायक रथ ने किया। डा. रथ ने जल से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सही योजना और राजनीतिक इच्छाशक्ति को जरूरी बताया। कार्यशाला के पहले सत्र की अध्यक्षता करते हुए डा. अनिल दीक्षित ने गंगा कार्य योजना के कई पहलुओं पर रोशनी डाली। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बी.पी. शुक्ला ने गंगा कार्ययोजना की उपलब्धियों और खामियों की चर्चा की। दूसरे सत्र की अध्यक्षता करते हुए क्राइस्ट चर्च के डा. एम बोसवाल ने नदियों को जोड़ने की परियोजना पर चर्चा की।

Concern over mismanagement of water resources in India

SEPTEMBER 27, 20

THE PIONEER

STAFF REPORTER
KANPUR

ALTHOUGH WATER is available in plenty yet to meet the demand it has to be supplied at places where it is most required. The major cause of concern was mismanagement of water resources as the governments have diverted water for economic use leading to environmental problems. Unless the 3Ps -- Pitfalls, Problems and Prospects are taken in the right earnest and water effectively managed the crisis was likely to cross the Rubicon. Thus the need of the hour is create awareness among the masses and students.

This was stated by Prof Binayak Rath, IIT-Kanpur, while addressing the two-day workshop on "Overcoming water scarcity and quality constraints" being organised by Eco Friends at the St Mary's Convent auditorium on Friday. Prof Rath specialises in cost-benefit analysis, environmental impact assessment and water resource management and is a globe-trotter who has carved a niche for himself in the field of water resource management world over.

Prof Rath said water scarcity is manmade and said this crisis was likely to reach a whopping figure of 105 million hectare metre by 2005. He said the government had formulated National Water Policy 1987 and Mission of linking Rivers 2003. Expressing concern over the government decision to link rivers of the country, he said "In my opinion the mega project of linking rivers will rather create more problems. He said if this move is given a practical shape then it may lead to the culmination of global conflicts, loss of agricultural land and R&R problems. Prof Rath said in the present prevailing circumstances in India there is all possibility that there will be large scale swindling of funds and out of the total allocated amount hardly 15 per cent may be utilised towards the cause.

Welcoming the chief guest, the Principal of the school, Sr. Smitha said access to clean water is fundamental but over one billion people lack safe domestic water supplies. She said over 335 million of world population lives in water stressed or water scarce countries. She lamented that water pollution adds enormously to the existing problems of water crisis and the pollution threat is grave especially when it affects the groundwater supplies where contamination was slow to dilute and purification measures were costly. She said: "I hope the endeavour of the St Mary's Convent students will motivate the other institutions and the masses to follow suit and make every possible effort to conserve water".

Prof Binayak Rath of IIT-Kanpur participating in the water conservation workshop at St Mary's Convent. *Pioneer*

Earlier, the students of the school presented a theme song "Pani Re Pani Tera Rang Kaisa" before the workshop was declared open. The school choir sang mellifluently leaving the audience mesmerised. Pairs of teachers and students representing 30 schools participated in the workshop.

The first session on "Ganga and Ganga Action Plan" was chaired by Dr Anil Dixit who spoke on the importance of Ganga and GAP. He invited the Environmental Engineer of Central Pollution Control Board, Mr BP Shukla to express his views. This was followed by noted celebrity of IIT, Dr Padma S Vanker, who discussed the impact of heavy metal pollution in the Ganga water and its impact on public health.

The second session was chaired by Dr M Boswal of the Christ Church College who expressed concern over the government decision to interlink rivers of the country. Dr Sudhirendar Sharma, water and energy expert and environmental journalist, presented a detailed discussion over the issue with pitfalls and little promise of the interlinking of river project. He was critical about its feasibility and social cost. Prof Bithin Dutta of the IIT and a specialist in water management said the project of river linking needed technical expertise and people's participation for its success. Kudos to students of SMC who acted as good hosts and reflected perfect discipline.

District Magistrate Arvind Kumar who was the chief guest failed to turn up as he had been summoned to Lucknow.

, 2005,

SWATANTRA BHARAT

सेन्ट मैरीज स्कूल में जल समस्या पर कार्यशाला

जल प्रबंधन के समाधान में हर स्तर पर जुड़ाव जरूरी

कानपुर, २६ सितम्बर (सं.)।

इको फ्रेण्डस संस्था ने सेन्ट मैरीज कान्वेन्ट स्कूल में जल की गुणवत्ता तथा उसका अभाव विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया कार्यशाला का शुभारम्भ आई आई टी के प्रोफेसर डा विनायक रथ ने किया।

डा. रथ ने जल प्रबन्धन में तीन कारण बताते हुये सही योजना राजनीतिक तथा सरकारी इच्छाशक्ति तथा जनता का जुड़ाव शामिल है को समाधान के लिए प्रायोजित किया। पहले सत्र में समायतित्व करते हुये डा. अनिल दीक्षित ने कहा कि गंगा तथा गंगा कार्य योजना के विभिन्न पहलुओं पर बोलते हुए वक्ताओं को आमंत्रित किया। गंगा कार्य योजना की समस्याओं तथा कठिनाइयों पर विस्तृत चर्चा संख्या में प्रमुख राकेश जायसवाल ने की। उन्होंने कहा कि २० प्रमुख नदी घाटियों में से ६ में जल उपलब्धता एक हजार घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो गयी है। जल की मात्रा घटती जा रही है। और मांग बढ़ती जा रही है। परिणाम स्वरूप व गुणवत्ता निरन्तर गिर रही है। सेन्ट्रल पाल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड के बी पी शुक्ला ने गंगा कार्य योजना की खामियों तथा उपलब्धियों की चर्चा की।

दूसरे सत्र में काइस्ट चर्च कालेज के प्रवक्ता डा एम बोसवाल ने अध्यक्षता करते हुए नदियों के जोड़ने के विकल्प पर डा. सुधीरेन्द्र शर्मा को आमंत्रित किया जो जल तथा ऊर्जा के विशेषज्ञ है तथा पर्यावरण विशेषज्ञ भी है। उन्होंने नदियों के जोड़ने की योजना में कठिनाइयों तथा लाभ का विश्लेषण किया। डा. शर्मा ने सामाजिक मूल्य तथा परियोजना की सफलता पर सवालियां निशान उठाया आई.आई.टी. के सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर डा. विपिन दत्ता जो प्रबन्धन के विशेषज्ञ है, ने आम जनता को परियोजना से जोड़ने का आहवान किया तथा जन आन्दोलन के माध्यम से इस योजना को सफल बनाने पर बल दिया।

कार्यशाला स्कूल के अध्यापक तथा तीस स्कूलों के छात्रों के प्रतिनिधित्व से संपादित हुई। स्कूल की प्रधानाचार्या सिस्टर स्मिता ने विशेषज्ञ तथा अतिथियों का स्वागत करते हुए जल के जीव तथा प्रकृति की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यशाला का सफल संचालन श्रीमती पी जी थौमस ने किया।

THE TIMES OF INDIA

Eco Friends workshop

SCHOOL TIME

Eco Friends started a two-day workshop at St Mary's Convent High School on 'overcoming water scarcity and water-quality constraints' here on Friday. The workshop was inaugurated by professor of Indian Institute of Technology (Kanpur), Binayak Rath. School teachers and students from over 30 schools in the city participated in it. Principal, Sister Smita, emphasized the need of water in life and nature.

Members in a two-day workshop on water scarcity and quality that is being organised by Eco Friends at St Mary's Convent High School in the city on Friday.

application of nano - technology in IT. The function was concluded with vote of thanks by Er. VB Singh Past Hony Secretary, The Institution of Engineers, UP State Centre.

Art of Astrological Predictions

A talk on "Art of Astrological" Predictions" was organised at IE (I), U.P. State Centre on May 11, 2005. Er. B.K. Gupta, FIE, Secretary, Institute of Rail Transport, RDSO, Lucknow was the speaker. He dealt at length on the various aspects of the subject including synchronization of horoscope to predict timely occurrence of events. Talk was very interesting & informative and well attended. Er. A.S. Kapoor, FIE, Chairman IE (I), U.P. State Centre was present on the Occasion.

Insights of Leadership

1. Leadership is the continuous process of influencing others to work willingly towards an organisation's goals, and to the best of their capabilities. Eight characteristics of principle - centred leaders as per Dr. Stephen R. Covey are :

   (i) They are continually learning. (ii) They are service oriented (iii) They radiate positive energy, (iv) They believe in other people (v) They lead balanced lives, (vi) They see life as an adventure, (vii) They are synergestic, (viii) They exercise for self-renewal.

2. A leader must be aware of the psycological games people play in organizations, with an open mind without preconceptions and judgements, like the awareness of road traffic while traveling on the road. Dr. Eric Beme, Father of Transactional Analysis, has suggested that most people spend a large proportion of their time and energy playing psychological games. One way to stop the games others play on us is to honestly admit the mistake we have committed, without being habitually defensive, and take corrective action immediately. Another way to stop game playing, is to give the recognition to the other people for their strengths and achievements, without dwelling on their weaknesses.

3. ***The Five Tantras of Pancha-Tantaras are :*** Mitrabhedam (Rift between friends), Mitralabham (The winning of friends for team spirit and social capital), Sandi-vigraham (Friendship with a former enemy is untrustworthy), Labhdanasanam (Presence of mind is essential during emergencies), Asamprekhya karitwam (Use of discriminative intelligence in the accomplishment of one's task in untested situations). Six stories were narrated with insights relevant to the modern management practices.

4. ***The leadership insights for modern management from panchatantra are :*** (i) Plan properly, Act adequately, Check promptly the effect of action, take corrective and preventive action to stop. (ii) Undesirable effects - Inadequate actions cause disturbed feelings and these in tim make one to enter into the neurotic spiral with failure multiplier. (iii) Use LOVE formula : L - Listen O - Observe V - Verify E - Empathise. (iv) Be a role model (v) Be tolerant at all times, as tolerance is defined by UNESCO as "Respect, Acceptance and Appreciation"

News from Local Centres

Kanpur

Water Resoures Day Celebration 2005

Water Resources Day was observed on April 16th 2005 at the premises of the Institution of Engineers (India) Local Centre, Kanpur. Dr. Binayak Rath, Prof. Deptt. of HSS Indian Institute of Technology, Kanpur was the Guest Speaker on this occasion and he delivered a Lecture on the topic "Issues & Challenges of Urban Water Supply System". Prof. Dinesh Narayan FIE Chairman, IEI Kanpur Local Centre, welcomed the guest, the participants present on the occasion. Prof. Keshav Kant, Ex. Chairman IEI Kanpur Local Centre gave the introduction of the Chief Guest.

Dr. Rath after establishing the primacy of water for sustenance of human beings, examined the contemporary debate going on the world in the water front. The world water scenario was examined in the contest of sustainable development and also issues debated in the various world forums were analysed. In the second part of the lecture he analysed the Indian Scenario and the problems faced in our Urban Areas. More particularly he examined the problems faced in our Metropolitan Cities with a focus on water management issues related to Kanpur. The drinking water supply position was critically examined with the various figures and photographs. Then he highlighted the findings of his study undertaken in the Jajmau area of the city, which uses the water from the common Effluent treatment Plant. The post evaluation results show a gloomy picture of the area. The various issues and challenges of the Governance of water management systems were highlighted and even the scope of public-private partnership was examined from different angles. Finally he argued that in order to improve the system of Governance there is a need to adopt a stake holders approach where there is a greater role to be played by agents like the Press/Mass media and the Civil Society comprising of NGOs, enlightened citizens/RWAs, Women associations, elected representatives and finally